Ok"k% 41(vad % 8 (vxLr % 2019(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

रेलवे के निजीकरण का विरोध

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सी.एल.डब्ल्यू.), चितरंजन

इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री (आइ.एफ.सी.), पेरम्बुर, चैन्ने

शोक संवेदना

कॉमरेड ए.के. रॉय

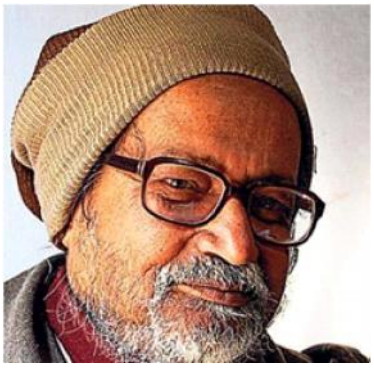

सीटू और कोयला मजदूरों के दिग्गज नेता कॉमरेड ए.के. रॉय के निधन पर सीटू को गहरा दुःख है; धनबाद से तीन बार के सांसद, बिहार विधान सभा में तीन बार के विधायक, संसदीय मंचों पर मजदूरों और दलित–शोषितों के मुद्दों को उठाने वाले अग्रणी नेता कॉमरेड ए.के. रॉय का धनबाद के बीसीसीएल अस्पताल में 81 साल की उम्र में निधन हो गया।

कॉमरेड ए.के. रॉय एफसीआई सिंदरी में एक योग्य इंजीनियर की नौकरी को त्यागकर अपनी युवावस्था में ही ट्रेड यूनियन आंदोलन से पूर्णकालिक तौर पर जुड़ गये थे। वह धनबाद–झरिया कोयला क्षेत्र में इसके निजी स्वामित्व के दिनों से ही कोयला मजदूरों के आंदोलन के अग्रदूतों और वास्तुकारों में से एक थे; उन्होने वर्तमान झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र धनबाद–बोकारो–हजारीबाग के मजदूरों और विस्थापितों के लिए संघर्ष किया।

कॉमरेड ए.के. रॉय सीटू से इसकी स्थापना के बाद से ही जुड़े थे, वह सबसे पुराने जनरल कौंसिल सदस्यों में से एक थे; और अपनी अंतिम सांस तक सीटू झारखंड राज्य समिति के संरक्षक रहे।

कॉमरेड ए.के. रॉय के निधन से मजदूर वर्ग के आंदोलन और विषेश रूप से सीटू को बड़ा नुकसान हुआ है। सीटू ने अपने दिवंगत नेता के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

सासंद की खरीद–फरोख्त के प्रयास पर अमित शाह को मुंहतोड़ जबाव

नई दिल्ली में मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठकर, भाजपा प्रमुख अमित शाह दूसरे दलों के सांसदों और विधायकों का व्यापार करते हैं।

यह खुलासा तब हुआ जब माकपा की राज्यसभा सदस्य और त्रिपुरा में महिला लोकतांत्रिक आंदोलन की नेता, झरना दास बैद्य ने 16 जुलाई को गृह मंत्री के कार्यालय में अमित शाह से मुलाकात की, और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के गुंडों और पुलिस व प्रशासन ने 27 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव की चल रही प्रक्रिया के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त करके, कानून के शासन के पूरी तरह से गुम होने के बारे में विस्तारित विवरण के साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। शारीरिक हमलों जिसमें हत्या, धमकी के चलते, पंचायतों की 85 प्रतिशत सीटों पर, सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को नामांकन पत्र जमा करने की अनुमति नहीं थी, और मुख्य रूप से निशाना सीपीआई (एम) को बनाया गया है।

बैठक में, इससे पहले कि झरना दास ज्ञापन सौंपें और उस पर खुली चर्चा करें, भारत के गृह मंत्री ने कहना शुरू कर दिया कि कम्युनिस्ट हर जगह समाप्त हो गए हैं और त्रिपुरा में सीपीआई (एम) समाप्त हो गयी है; और फिर झरना दास को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा।

झरना दास ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने आए हैं, भाजपा प्रमुख से नहीं; वह अपने व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि त्रिपुरा की जनता की गंभीर समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आयी हैं और जब तक सीपीआई (एम) का एक भी सदस्य जीवित है, तब तक आपकी पार्टी के खिलाफ वैचारिक संघर्ष जारी रहेगा।

शर्मसार अमित शाह को माकपा सांसद झरना दास वैद्य से 'सॉरी' कहते हुए माफी मांगनी पड़ी; और आश्वासन दिया कि वह जल्द ही त्रिपुरा का दौरा करेंगे और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देगें।

बाद में, सीपीआई (एम) सांसद टी.के. रंगराजन के साथ झरना दास ने प्रेस के सामने इन सभी तथ्यों का खुलासा किया।

सम्पादकीय

सीटू मजदूर

lhvkbVh; dk e[ki=

अगस्त 2019

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे एस मजुमदार~~

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

Hkkjrh; jksyo dk futhdj.k	5
LVhy etnwjksa }kjk fojks/k	7
gekjk jkLrk	8
&riu lsu	
Hkkjrh; etnwj vkUnksyu o	
loZgkjk vfrjk"Vªh; rkokn	13
&Lons'k nsojksa;	
jkT; ljdkj deZpkfj;ksa	
dh ,drk o lq?k"kZ	21
&lqHkk"k ykcck	
jkT;ksa ls	24
,d vihy	26

भारत को बेचने की मुखालफत कीजिये

Hkkjr dh Hkwfe] bldh py&vpy lEifÙk dkiksjsV~l dks cspk tk;sxhA Hkkjr dh lEçHkqrk fonsf'k;ksa ds gkFkksa fxjoh j[kh tk;sxhA dsUnzh; ctV 2019 dk [kkdk ;gh gSA;g lc dsæh; foÙk eU=h }kjk viuk ctV Hkk"k.k esa mNkyk x, ^^5 fVªfy;u #i;k ¼5 yk[k djksM #i;k½ dh vFkZ0;oLFkk** cukus dh ?kk"k.kk dh vksj esa fd;k tk jgk gSA ;g ^^5 fVªfy;u #i;k dh vFkZ0;oLFkk** ,d cMk /kks[kk gSA bldk edln ns'kh vkSj fonsZ'kh dkiksjsV~l ds fy, NIijQksM esa eukQk dk bZrtke djuk gS vkSj mlds fy, dkjikjsV ijLr ^^Je l/kkjk** dk ,yku fd;k x;k gSA

eksnh&1 ljdkj lHkh ekSpksZ ij foQy jgh gS(nsZ'k xHkhj foÙkh; ?kkVs esa gS vkSj vFkZ0;oLFkk yM[kM+k jgh gSA vc eksnh&2 ljdkj nsZ'k dh egkurd'k turk ds dfBu Je ls vftZr jk"Vªh; lEink dks cspus dh gMcMh esa gSA gksbZ vìs vMkuh dks lksSai fn;s x;s gSA jkst ;k=k djus okys djksMksa gkfl;s ij iMs fgUnqLrkfu;ksa dh thou j{kk & jksy] turk ds fy, ljdkjh lsok ds LFkku ij dkjikjsV ds fy, eukQk mxyus okys m|e esa cnyh tk jgh gSA

jksyo vkSj cSp&tkus&okys lHkh lkoZtfud m|ksxksa dh c'kdheh tehu Hkh fu'kkus ij gSA ctV esa vyx&vyx LFkkuksa ij Ñf"k mRikn Ák|kfxdh dsUnzksa [kksyus dk ÁLrko gS tks njvly [ksrh dh tehu dks dCtk djus vkSj lsZ ij ekyks o [kksus dk lksSkeku cukus okyh cgqjk"Vªh; dEifu;ksa dh llykbZ ykbus [kksyus ds fy, gSA

eksnh ljdkj us ^^Hkkjrh; —f"k ds :ikarj.k ds fy, eq[;ef=;ksa dh gksbZ ikoj deZVh** xfBr dh gSA egkjk"Vª ds eq[;e=h QM+.kohl bldk v/;{k gSA U;wt ,tsalh ihVhvkbZ ds vuqlkj bl deZVh ds fu"d"kksZ dh ckjs esa crkrs gq, QM+.kohl us 19 tqykbZ dks dgk fd ^^cSBd esa cqvkbZ ls ysdj fcØh rd dh lkjh çfØ;k ds fMftVykbZsku] mlesa rduhd ds dkjxj bLrsekyksa dh ckjs esa ppkZ gq;h - - -A** QM.kohl us ;g Hkh dgk fd ^^—f"k ds {ks= esa futh fuos'k ¼i<s(dkjikjsV fuos'k½ vkSj Bsdk [ksrh dks çkRlkfgr djus dh vko';drk gSA**

Hkkjr dh lçHkq çfrHkfr;ksa ¼lkofju½ ckM+l] fonsZ'kh eæk cktkj esa fcdus ds fy, [kksy fn;s x, gSa ftlls Hkkjr ofZ'od vkfFkZd lqidV ds [krjksa ds lkeus vk tk;sxkA oghaa nwljh rjQ lkSa çfr'kr çR;{k fonsZ'kh fuos'k ¼,QMhvkbZ½ ds jkLrs ls chek bUVjehfM;jhs ds fy, rqjar 100% rFkk chek] foekuu] ehfM;k o flusek dk.M fjVsy esa ,QMhvkbZ dks vkSj T;knk c<+kdj fonsZ'kh dsifu;ksa dks Áos'k vklku cuk;k tk jgk gSA lkoZtfud m|ksxksa ds U;wure 25% bfDoVh fofuos'k dks c<+kdj 35% dj fn;k x;k gS] rkfd fonsZ'kh lLFkkxr fuos'k ¼,QvkbZvkbZ½ ds jkLrs ls cgqjk"Vªh; dsifu;ksa dks Áos'k djk;k tk ldsA

ukdke dkjikjsV dsifu;ksa [kksn dks vfLrRo cpkus ds fy, chek ds jkLrs ls lkoZtfud /ku ij fuHkZj dj jgh gSa vkSj jk"Vªh; lEink rFkk lsZlk/kuksa dks gMi+iuk pkgrh gSa(tcfd ljdkj lkekftd lsokvksa dks futh chek dsifu;ksa ds gokys dj jgh gSA ç/kkuea=h Qly chek ;kstuk] vk;q"eku Hkkjr LokLF; ;kstuk vkfn chek nykyksa ds fy, rqrh ls [kSyrs cktkj gSA blhfy,] chek bUVjehfM;jhs esa 100% ,QMhvkbZ ds ÁLrko ds pyrs fonsZ'kh nykyksa ds Áos'k ds dkj.k Hkkjrh; Ñf"k o tu LokLF; esa rckgh ep tk,xhA

vkb;s] igyh dsæh; VªsM ;fu;u ds bl 'krkZnh o"kZ esa ge fgUnqLrku esa etnwj oxZ ds mu l?k"kksZa dks ;kn djs tks mlus viuh thou n'kkvksa dks l/kkjus] vf/kdkj gkfly djus vkSj vxzsth jkt dh xqykeh ls vktknh ikus ds fy, fd;s FkA etnwj oxZ ds bu l?k"kksZa us geas fl[kk;k gS fd Hkkjr ds etnwj oxZ ds fy, mlds nsZ'k dh lEçHkqrk] ,drk vkSj fgr lokZPp gSA

vkb;s] ge l?k"kksZa ds ml cqjs dks Åpk djsa(Hkkjr dks cspus dh eq[kkyQr djsa(Hkkjr dks fonsZ'kh vkSj nsZ'kh dkjikjsV ds pxqy ls eqä djkus dk ,yku djsA

सीटू सचिवमंडल की बैठक के निर्णय

नई दिल्ली; 17–18 जून, 2019

1. सचिवमंडल ने सीटू के स्वर्ण जयंती वर्ष को मनाने के लिए एक वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया है।
2. सीटू का 16वाँ सम्मेलन 23–27 जनवरी 2020 को चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। 7–10 अगस्त, 2019 को कर्नाटक के हासन में आयोजित होने वाली सीटू की जनरल काउंसिल (जीसी) की बैठक सम्मेलन के विवरण को अंतिम रूप देगी।
3. अखिल भारतीय सम्मेलन से पहले सभी राज्य कमेटियों को अपने सम्मेलनों को पूरा करना चाहिए।
4. सभी राज्य कमेटियों को 2018 तक के एनुअल रिटर्न के साथ यूनियनों की संबद्धता का नवीनीकरण 31 जुलाई, 2019 से पहले सीटू केंद्र को भेजना चाहिए, ताकि सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल के बारे में अंतिम रूप देने के लिए जीसी बैठक सक्षम हो सके।
5. सभी राज्य कमेटियों से अनुरोध है कि जनवरी 2019 में आयोजित विस्तारित सचिवमंडल की बैठक में दिए आश्वासन के अनुसार, पी.आर. भवन और गाजियाबाद भवन की निधि का अपना कोटा पूरा करें।

सरकार ने लघु बचत की ब्याज दर में कटौती की

लाखों लोगों का जीवनयापन प्रभावित

सीटू ने 29 जून को एक बयान में, वर्तमान वित्तीय वर्ष की जुलाई–सितंबर की तिमाही के लिए 10 मूल अंकों से आगे की छोटी बचत की ब्याज दर में कटौती के लिए भाजपा–एनडीए की मोदी–2 सरकार की कड़ी निंदा की है। यह निर्णय लाखों आम और गरीब जनता, वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत व्यक्तियों के जीवन भर की बचत पर होने वाली कमाई, जो उनके अस्तित्व का प्रमुख साधन है, में तेज गिरावट के माध्यम से भारी चोट की जा रही है।

सरकार ने छोटी बचत की ब्याज दरों के बारे में हर तिमाही में निर्णय लेने की घोषणा की है, जो इस पर निर्भर जनता के जीवनयापन में अस्थिरता पैदा करेगा।

सरकार का यह निर्णय आम जनता की बचतों को राज्य–संचालित सुरक्षित लघु बचत साधनों से हटाकर शेयर बाजारों सहित, सट्टेबाजी की व्यवस्था के लिए ही लिया गया है। यह मोदी सरकार की ओर से निजी निवेशकों के लिए सस्ती पूंजी की खैरात है।

सीटू ने इसे वापस लेने की मांग की है; और अपने संबद्धों को निर्देशित करते हुए और पूरी ट्रेड यूनियन बिरादरी से अपील की कि वे इसकी निंदा में अपनी आवाज बुलन्द करें।

लघु बचत योजनाऐं		
बचत योजनाऐं	ब्याज दरें (2019) (प्रतिशत में)	
	1 जुलाई – 30 सितम्बर	1 अप्रैल – 30 जून
बचत जमाऐं	4.0	4.0
1–वर्षीय सावधि जमा	6.9	7.0
2–वर्षीय सावधि जमा	6.9	7.0
3–वर्षीय सावधि जमा	6.9	7.0
5–वर्षीय सावधि जमा	7.7	7.8
5–वर्षीय आवर्ती जमा	7.2	7.3
5–वर्षीय वरिष्ठ नागरकि बचत योजना	8.6	8.7
5–वर्षीय मासिक आय खाता	7.6	7.7
5–वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र	7.9	8
जन भविष्य निधि योजना	7.9	8
किसान विकास पत्र	7.6 *(परिपक्वता अवधि 113 माह)*	7.7 *(परिपक्वता अवधि 112 माह)*
सुकन्या समृद्धि खाता योजना	8.4	8.5

(सौजन्य; बिजनेस लाइन; 28 जून, 2019)

भारतीय रेल का निजीकरण

भारतीय रेलवे के निजीकरण का प्रतिरोध करोः सीटू

9 जुलाई को तुरंत, सीटू ने मोदी सरकार के भारतीय रेलवे के निजीकरण के कदम का पुरजोर विरोध किया, जिसमें 100 दिन की कार्ययोजना भी शामिल है, जिसमें प्रस्ताव दिया गया है :–

(1) निजी यात्री गाड़ियों को संचालित करने, जिसमें ज्यादातर प्रमुख ट्रेनें हैं और इसके वास्ते 4 महीने के अंदर निविदाए जारी करने; (2) दो यात्री गाड़ियों को आईआरसीटीसी द्वारा संचालित करने के वास्ते 100 दिनों के अंदर सौंपने; (3) रेलवे की कीमती भूमि को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण को पट्टे पर देने; (4) करोड़ों वंचित, कड़ी मेहनत करने वाले दैनिक भारतीय यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी को प्रमुख सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, रेलवे से हटाने के वास्ते 'इसे त्याग दो' अभियान के तहत रेलवे के किराए में वृद्धि की शुरुआत ताकि देशी–विदेशी कॉरपोरेट्स को उनके मुनाफों को बढ़ाने का मौका दिया जाये; (5) संबद्ध कार्यशालाओं सहित 7 उत्पादन इकाइयों का 'इण्डियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी' में निगमीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की स्वदेशी निर्माण क्षमता की हत्या करके, उत्पादन को निजी क्षेत्र में आउटसोर्स करने का पहला कदम है।

सीटू ने आम जनता और अपनी यूनियनों और फेडरेशनों का विरोध करने के लिए आह्वान किया है कि एकजुट होकर इस कदम का प्रतिरोध करें।

संसद में रेलवे निजीकरण

2 जुलाई को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान, इस मुद्दे को उठाते हुए, सीटू नेता और सीपीआई (एम) के सांसद, टीके रंगराजन ने रखरखाव सहित रेलवे की सभी विशाल उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण और रेलवे प्रिंटिंग प्रेस इकाइयों को बंद करने के सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया। और कहा कि यह विदेशी निवेशकों सहित कॉर्पोरेट्स के पक्ष में निजीकरण का रास्ता है। अपने संक्षिप्त हस्तक्षेप के माध्यम से, सीटू के राष्ट्रीय सचिव और सीपीआई (एम) के सांसद ई. करीम ने सदन को सूचित किया कि चितरंजन लोकोमोटिव में मजदूर आंदोलन पर हैं और सरकार के फैसले के विरोध में रायबरेली इकाई में मजदूर हड़ताल पर हैं।

इस कदम का विरोध करते हुए, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मार्डन कोच फैक्ट्री का पिछले दरवाजे से निजीकरण करने के सरकार के प्रयास का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों में अनिश्चितता और भारी बेरोजगारी पैदा होगी।

रेल निजीकरण विरोधी संघर्षः एक जन आंदोलन

18 जुलाई को, सीटू ने अपनी सभी इकाइयों, यूनियनों और फेडरेशनों का, रेलवे के निजीकरण के किसी भी रूप में विरोध करने और इसे जन आन्दोलन के रूप में बदलने के लिए देशव्यापी एकजुट संघर्ष को शुरू करने का आह्वान किया।

आरंभ करने के लिए, सीटू ने सभी संगठनों से संबद्ध सभी ट्रेड यूनियनों, डी.आर.इ.यू. और ए.आइ.एल.आर.एस.ए. सहित सीटू से संबद्ध व जुड़ी रेलवे मजदूरों की सभी यूनियनों तथा मेहनतकश जनता किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों सहित सभी के जनसंगठनों, पेशेवरों के संगठनों, स्व–रोजगार में लगे लोगों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के संगठनों, और अन्य सभी जो शामिल होना चाहें को व्यापक स्तर पर एकजुट करते हुए व्यापक स्तार के आधार पर पीपुल्स कन्वेंशन के आयोजन का सुझाव दिया है।

कन्वेन्शन के बाद, रेलवे प्रतिष्ठानों के समक्ष और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के सभी तबकों को लामबंद किया जाना चाहिए, और जैसा भी स्थानीय स्तर पर तय किया जाये।

सीटू की पहल पर, जनता के लिए लाखों हैंडबिलों को छपवाना और वितरित किया जाना चाहिए। सीटू जल्द ही रेलवे के निजीकरण के सभी पहलुओं के साथ रेलवे पर पुस्तिका प्रकाशित करने का प्रस्ताव करता है।

देशव्यापी विरोध

वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू), चित्तरंजन में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू), रायबरेली में आधुनिक कोच फैक्टरी (एमसीएफ), कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) चेन्नई के पेरम्बूर में रेलवे कर्मचारी पहले ही काले झंडे के प्रदर्शन के साथ आंदोलन शुरू हो चुके हैं, उनमें से कुछ हड़ताल पर हैं, और कई रेलवे यूनियनों ने रेल निजीकरण के खिलाफ विरोध आंदोलन भी चलाया है। अन्य उत्पादन इकाइयाँ पटियाला में डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स (डीएमडब्ल्यू) और बेंगलुरु में रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ) हैं।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स लेबर यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में, मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन रैलियां निकालीं और कारखाने के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। रायबरेली में एमसीएफ के मजदूर मध्याह्न अवकाश के दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं और 2,500 मजदूरों ने महानिदेशक कार्मिक के दौरे के दौरान प्रदर्शन किया।

वाराणसी में डीएलडब्ल्यू के मजदूर कई दिनों तक हड़ताल पर रहे। डीएलडब्ल्यू मजदूर यूनियन और एआइसीसीटीयू के अर्ध–नग्न मजदूरों ने संयुक्त रूप से 7 जुलाई को उनके निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान एक विरोध प्रदर्शन किया।

कपूरथला के मजदूरों ने विशाल रैली निकाली और काला झंडा प्रदर्शन किया। पेरम्बूर में आइसीएफ के गेट पर विशाल प्रदर्शन ने कारखाने में काम रोक दिया। चेन्नई में, सभी ट्रेड यूनियनों की संघर्ष समिति ने 5 जुलाई को आइसीएफ के गेट पर 5000 मजदूरों के जुलूस और प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसे सीटू, इंटक, बीएमएस, एचएमएस और एलपीएफ के नेताओं ने संबोधित किया।

रेलवे बोर्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय प्रबंधन के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी के बावजूद, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआइएलआरएसए) के सदस्यों ने सभी मंडल मुख्यालयों पर 15–16 जुलाई को 24 घंटे की भूख हड़ताल की जिसमें रेलवे के अंदर और बाहर के विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेता शामिल हुए। रेनिगुन्टा में एनएफआइआर के महासचिव राघवैया; पूर्व सांसद ए. संपत, डीवाईएफआई केरल राज्य सचिव ए. रहीम और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और मजदूरों के परिसंघ (सीसीजीइडब्ल्यू) के महासचिव एम. कृष्णन ने तिरुवनंतपुरम में; बेफी नेता सी.पी. कृष्णन, एआईडीईएफ के महासचिव सी श्रीकुमार, डीआरईयू के एडीएस बालासुब्रमण्यम; विजयवाड़ा में सीटू के राज्य नेता आर. अजय कुमार और अन्य सहित ने हड़ताली कर्मचारियों को संबोधित किया।

दक्षिण रेलवे एम्पलाईज यूनियन (डीआरईयू) ने चेन्नई, मदुरै, सलेम और त्रिची में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया।

ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआइआरएफ) और इसके संबद्धों ने 1 से 6 जुलाई तक सप्ताह भर चलने वाले 'ब्लैक डे' कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नेतष्त्व इसके महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने किया और इनके सहयोगी एनआरएमयू के महासचिव वेणु पी नायर के नेतृत्व में 1 जुलाई को मुंबई में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ।

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआइआर) के वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने भी 12 जुलाई को मुंबई के चर्चगेट से विरोध मार्च निकाला।

इस्पात मजदूरों का प्रतिरोध

सेल के विशेष इस्पात संयंत्रों की बिक्री के खिलाफ

5 जुलाई को एक बयान में, सीटू ने सेल के सभी तीन विशेष स्टील्स प्लांटों पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मिश्र धातु इस्पात संयंत्र (एएसपी), तमिलनाडु के सलेम में सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी), और कर्नाटक के भद्रावती में विशेश्वरैया आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड (वीआईएसएल), का निजीकरण करने के लिए भाजपा–एनडीए सरकार के कदम की निंदा की और सरकार के इस कदम के खिलाफ इस्पात मजदूरों की हड़ताल और आंदोलन का स्वागत किया; और देश के मजदूर वर्ग का एकजुट होकर सरकार के ऐसे कदम का विरोध करने का आह्वान किया।

गंभीर वित्तीय दबाव के बावजूद, एएसपी ने प्रतिरक्षा और परिशुद्ध इंजीनियरिंग कार्य के लिए विशिष्ट गुणवत्ता वाले मिश्र धातु इस्पात का निर्माण करता रहा है। सलेम स्टील उच्च गुणवत्ता के स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करता है और इसी तरह का भद्रावती संयंत्र भी है।

मंत्रालय के निर्देश पर सेल ने 4 जुलाई को एक अधिसूचना जारी करके निजी क्षेत्र के संभावित विदेशी और घरेलू खरीदारों से 'एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट' को आमंत्रित किया गया था। यह स्टेनलेस स्टील सहित विशिष्ट स्टीलों के पूरे बाजार को सौंपने की एक चाल है, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ, बड़ी राष्ट्रीय संपत्तियों को एक थाली में सजाकर कॉर्पोरेट्स को और निजी हाथों में स्थानांतरित करना है।

भाजपा–एनडीए सरकार ने, अपने पिछले कार्यकाल में, इन तीनों संयंत्रों का निजीकरण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस्पात मजदूरों, विशेष रूप से दुर्गापुर, सलेम और भद्रावती के मजदूरों द्वारा देशव्यापी प्रतिरोध संघर्ष के कारण विफल रही।

जैसे ही टेंडर नोटिस की खबर फैली, सलेम के एसएसपी मजदूरों ने 24 जुलाई को हड़ताल की और दुर्गापुर में स्टील कर्मचारियों ने 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन रैलियां और रोड रोको आयोजित किए। एसएसपी, एएसपी और वीआईएसएल मजदूर और सेल व आरआईएनएल के सभी मजदूरों के विरोध करने और प्रतिवाद करने के अवसर पर बढ़ रहे हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन ने भी एकजुटता कार्रवाहियाँ की हैं।

सलेम हड़तालः 4 जुलाई को, मोदी सरकार ने अन्य सीपीएसयू के साथ सेलम स्टील प्लांट की रणनीतिक बिक्री के लिए वैश्विक निविदा मंगाई। इसका विरोध करते हुए, सलेम स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने मुकम्मल हड़ताल की और कारखाने के गेट के सामने प्रदर्शन किया। रानीपेट और त्रिची की इकाइयों में भेल के सीपीएसयू मजदूरों ने सलेम इस्पात मजदूरों के साथ एकजुटता में प्रदर्शन किया।

दुर्गापुर में विरोध प्रदर्शनः 5 जुलाई को कारखाने के गेट पर धरना प्रदर्शन में मजदूरों के शामिल होने के कारण, सुबह की पाली से ही प्लांट में काम बंद हो गया। आंदोलनकारी मजदूरों ने पुलिस के हस्तक्षेप के बाद 5 घंटे बाद सड़क को बंद कर दिया।

एसडब्ल्यूएफआइ का विरोधः सीटू के एसडब्ल्यूएफआइ (स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) के आह्वान पर सभी ट्रेड यूनियनों ने 12 जुलाई को एएसपी परिसर के अंदर और जीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। देश के विभिन्न हिस्सों में सभी सेल इकाइयों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए थे।

चेन्नई में ट्रेड यूनियनों का संयुक्त विरोध प्रदर्शनः 18 जुलाई को, सभी ट्रेड यूनियनों ने विषेश रूप से सेलम के इस्पात संयंत्रों की बिक्री के खिलाफ चेन्नई में 20,000 मजदूरों की एक मजबूत संयुक्त रैली और प्रदर्शन किया। सभी ट्रेड यूनियनों के झंडे और बैनर के साथ चेपक स्टेडियम से एक विशाल जुलूस निकाला गया। रैली में सरकारी कर्मचारी शामिल हुए और यह रैली विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित थी। सीटू के प्रदेष अध्यक्ष ए. सौन्दराजन और महासचिव जी. सुकुमारन; एलपीएफ, इंटक, बीएमएस, एलएलएफ, ओबीसी एसोसिएशन और कॉंग्रेस राज्य अध्यक्ष व पूर्व सांसद के.वी. थांगकाबालू और अन्य नेता उपस्थित थे।

संघर्ष व बलिदान के 100 वर्ष

मजदूर वर्ग की एकता के लिए लड़ाई के 50 वर्ष

हमारा रास्ता

तपन सेन

17वीं लोक सभा के चुनावों के बाद, जिसमें फिर से आर. एस. एस नेतृत्व की मोदी सरकार कहीं बड़े और निर्णायक जनादेश के साथ पुनः सत्ता में आयी है, हम एक बहुत ही कठिन मुकाम पर हैं। इसने समूचे मजदूर वर्ग बल्कि समूची आम जनताा के सामने आर्थिक,राजनीतिक व सामाजिक मोर्चों पर एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

लोक सभा चुनावों के पहले के लगभग ढ़ाई वर्षों में सीटू के स्वतंत्र अभियानों व संघर्षों के साथ ही लगातार संयुक्त ट्रेड यूनियन कार्रवाईयॉ हुई थीं इसके अतिरिक्त किसान व खेतमजदूर संगठन भी इस दौरान अपने संयुक्त आंदोलनों में सक्रिय रहे थे। इसके साथ–साथ हड़तालों समेत कितने ही उद्योग/सैक्टर आधारित आंदोलन भी हुए थे। इसी क्रम में 5 मार्च, 2019 को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों का संयुक्त कन्वेंशन हुआ जिसमें सर्वसम्मति से 'मजदूरों का माँगपत्र' पारित किया गया और आर्थिक नीति निजाम की दिशा को ही बदलने तथा 'मजदूर–विरोधी, जन– विरोधी, राष्ट्र विरोधी मोदी सरकार को बाहर करने का आह्वान किया गया था। यह पहली बार था जब केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों के संयुक्त मंच से सरकार को हटाने का आह्वान किया गया। सीटू ने इसमें अहम भूमिका निभायी। तथापि, यह आह्वान पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसे सूक्ष्म स्तर पर हमारे सचेत व सक्रिय संगठनात्मक हस्तक्षेप के द्वारा आम मेहनतकश जनता तक नहीं पहुँचाया जा सका। 'जिन तक नहीं पहुँचे उन तक पहुँचो' तथा 'मुद्दों को नीतियों से जोड़ने तथा उन नीतियों को आगे बढ़ाने वाली राजनीति का पर्दाफाश करने' का हमारा आह्वान हमारे मजबूत राज्यों तक में प्रभावी रुप से अमल में नहीं लाया जा सका। यह एक गंभीर आत्मविश्लेषण की मांग करता है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे।

गंभीर आत्मविश्लेषण समय की मॉग

इससे हमें एक ठोस सबक मिलता है। राजनीतिक स्तर पर दुश्मनों की पहचान करने के लिए अकेले संघर्ष अपने आप राजनीतिक चेतना पैदा नहीं कर सकते हैं, हालांकि, संयुक्त संघर्षों में मजदूरों की सक्रिय भागेदारी इस तरह की चेतना को प्राप्त करने के लिए जरुरी पूर्वशर्त है। मेहनतकशों के बीच राजनीतिक चेतना पैदा करना, जिसमें आवश्यक रुप से सभी बीमारियों व मुसीबतों की जड़ के रुप में शोषणकारी पूंजीवाद व्यवस्था की उनके द्वारा पहचान जिसमें शासन में राजनीतिक एजेंट काम कर रहे होते हैं, एक ऐसा कार्य है जिसे अलग से और सचेत रुप से हाथ में लिया जाना है और मजदूर वर्ग के आंदोलन की आगे बढ़ी हुई कतारों जो वास्तव में निरंतरता के साथ संघर्ष की अगुवाई कर रही हैं, के द्वारा गंभीरता पूर्वक पूरा किया जाना है।

हमें अपने भीतर यह तलाश करनी होगी कि इस कार्य के प्रति हम अपनी कार्रवाईयों व गतिविधियों में कितने सचेत व केन्द्रित रहे, किस हद तक हमारी समझदारी में मेहनतकशों के समक्ष उपस्थित मुद्दों को नवउदारवादी नीति निजाम से जोड़ पाने और इन नीतियों को आगे बढ़ाने वाली राजनीति का पर्दाफाश करने की फौरी आवश्यकता को आत्मसात कर पाये और इसे आम मजदूरों व जनता की चेतना तक ले जा पाये। दिक्कतें केवल इस चेतना विशेष से संबंधित परियोजना के साथ आम मजदूरों तक पहँचने में हमारी संगठनात्क कमियों की ही नहीं हैं, बल्कि इसकी तात्कालिकता को महसूस कर संगठन के हर स्तर पर इसे प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने में भी है। इस बुनियादी कार्य को करने का कोई छोटा रास्ता नहीं है।

2019 का आम चुनाव, जनता के अधिकारों व जीविका पर, पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर, जनता की एकता व भारतीय समाज की अखंडता पर, घरेलू संस्थाओं व संविधान के बुनियादी सिद्धांतों पर शासक वर्गों के फासीवादी हमलों की पृष्ठभूमि में पूरी तरह से एक अलग तरह की राजीनिक लड़ाई थे। ये सभी अभिन्न रुप से एक दूसरे से जुड़े हैं और साख खो चुकी नवउदारवादी व्यवस्था द्वारा व्यवस्थागत संकट में अपने आपको बचाने के लिए इन्हें आजमाया गया है। इससे केवल मजदूर वर्ग की विचारधारा के आधार पर एक स्पष्ट राजनीतिक निशाने के साथ, एक व्यापक व विस्तृत दृष्टिकोण के साथ तथा सूक्षम योजना के साथ अपने काम को परिस्थिति के अनुकूल बनाकर ही निबटा जा सकता है। इसी समझदारी के साथ सीटू ने चुनावी लड़ाई में सामूहिक रुप से अपने कार्यों को ठोस रुप दिया था।

एक मजदूर वर्ग के संगठन के तौर पर, जनता के पास जाने की व्यापक पहुँच के साथ जमीनी स्तर पर हमारी सभी इकाईयों को 'मजदूरों के माँगपत्र' का प्रयोग करते हुए मजदूरों के बीच व कार्यस्थलों पर सघन अभियान चलाना था। हालांकि यह एक संयुक्त ट्रेड यूनियन माँगपत्र था परन्तु इसमें नीति निजाम को नवउदारवाद के विकल्प की ओर बदलने के आवहान के रुप में इसकी राजनीतिक विषय वस्तु गंभीर थी। इसी काम में मजदूरों से सीधे जुड़े मुद्दों को उठाया जाना था, उन्हें मोदी सरकार द्वारा आक्रामक ढंग से आगे बढ़ायी गयीं नवउदारवादी नीतियों से जोड़ना तथा मुसीबतों की जड़ की एकीकृत समझदारी बनने को छिन्न–भिन्न करने तथा समाज को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल का भंडाफोड़ करना भी था। इस काम को पूरा करने के लिए हमें, विभिन्न मुद्दों के बारे में निचले स्तर पर अपने कैडरों को समझदारी से लैस करने के लिए 'बातचीत के बिन्दुओं' व परचों का व्यापक प्रयोग करना था।

हमें आत्मालोचना के साथ यह परीक्षण करना होगा कि एक मजदूर वर्ग के संगठन के रुप में किस हद तक हम अपने कामों को पूरा कर पाये और किस हद तक हम सीटू की वर्गीय समझ को जनमानस तक ले जा पाये। अपने आपको और मजदूर वर्ग को राजनीतिक सांगठनिक रुप से आगे आने वाली लड़ाईयों के लिए तैयार करने के लिए यह आवश्यक है। हमारी राजनीतिक विचारधारात्मक समझदारी तथा संगठन के बारे में कोझिकोड दस्तावेज समेत संबंधित दस्तावेज हमें अवश्य ही इस दिशा की ओर निर्देशित करेंगे।

चौतरफा आक्रामण होना तय है

मोदी सरकार जिसने अपने पहले कार्यकाल में असहमति की आवाजों को दबाकर तथा जनता के बुनियादी जनवादी अधिकारों पर हमला कर बड़े कारपोरेटों व व्यापारिक घरानों, अंतराष्ट्रीय वित्त तथा साम्राज्यवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया उससे इस बार कहीं ज्यादा आक्रामक व बर्बर होने की उम्मीद ही की जा सकती है। संसद में बड़े बहुमत और उसके साथ नवउदारवाद के बारे में मुख्य विपक्षी दलों का सुस्त दृष्टिकोण वे हथियार हैं जो पहले ही उनके पास हैं और जिनके द्वारा सरकार हेकड़ी के साथ जनवादी प्रक्रियाओं व संस्थानों को ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करेगी।

केन्द्रीय बजट में बड़े बहुमत की यह हेकड़ी स्पष्ट को चुकी है। जब देश की अर्थव्यवस्था, वास्तविक अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए निवेश में ठहराव, देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी दर जिसमें रोजगार की दर 45 वर्षों में सबसे कम है के साथ लगातार मंदी की ओर फिसलती जा रही है तब बजट प्रस्तावों में इनमें से जनता की किसी भी बुनियादी समस्या को किसी रुप में भी संबोधित करने की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। आम जनता की बिगड़ती हालत के कारण घटते उपभोग स्तर और परिणामस्वरुप घरेलू बाजारों के आकार के सिकुड़ने की बुनियादी समस्या जिसके चलते उद्योगों व सेवाओं की मौजूदा क्षमता के उपयोग में हुई कमी से रोजगारों व आजीविका के बढ़ते नुकसान ने मंदी– संकट–गरीबी– प्रभावी माँग संकुचन – और अधिक मंदी का ऐसा चक्र चला दिया है जिस पर बजट में कतई ध्यान नहीं दिया गया है।

बजट जहाँ बड़े बिजनेस घरानों– कारपोरेट लॉबी पर और ज्यादा रियायतों व छूटों की बरसात करने पर केन्द्रित रहा है वहीं कल्याणकारी व सामाजिक कल्याण व सेवाओं पर खर्च में कटौती की गयी है और राष्ट्रीय संपदाओं तथा उत्पादन केन्द्रों के कौड़ियों के दाम आक्रामक निजीकरण को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस सबका एक ही उद्देश्य है– करोड़ों जनता से छीन कर ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का मुट्ठीभर बड़े व्यापारी कारपोरेटों – भूस्वामी हित समूहों को हस्तातरंण। इससे समाज में आय असमानता अश्लील स्तर तक बढ़ेगी जिससे संकट और गहरा होगा। नवउदारवाद का सार यही है।

शासक वर्गों की परियोजना का वास्तविक अर्थ

हमें, आर्थिक नीति निजाम में इस तरह के अक्खडपन का अर्थव्यवस्था व जनता पर पड़ने वाले इसके असर तथा राजनीतिक व सामाजिक मोर्चों पर इसके परिलक्षण का वास्तविक अर्थ समझने की जरुरत है।

भाजपा सरकार के पिछले पाँच वर्ष सभी आर्थिक मानकों व संकेतकों में बराबर व लगातार गिरावट के वर्ष रहे हैं। विदेशी व देशी दोनों ही तरह से कारपोरेटों को जारी उदार रियायतों के बावजूद पूंजीगत मालों व अन्य प्रमुख व रणनीतिक सेक्टरों समेत, निवेश में बराबर गिरावट दर्ज की गयी है। विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा गिरावट है। बेरोगारी ओर रोजगार की हानि अपने चरम पर हैं और इनमें सुधार के कोई चिह्न दिखायी नहीं पड़ रहे। मेहनतकश आबादी की औसत आय में पूरी तरह से ठहराव है जिसका मतलब वास्तविक अर्थों में गिरावट है। केवल सुपर धनी व बड़े बिजनेस/ कारपोरेट लॉबी की धन– दौलत में, मुनाफों में बृद्धि दिखायी दे रही है जो आय असमानता को अश्लील स्तर पर ले जा रही है। बड़े भूस्वामी भी अपने सहयोग व मिलीभगत के संदर्भ में कारपोरेट क्लब में शामिल हो रहे हैं। वे उत्पादन के तरीके को बदलकर उसे ज्यादा से ज्यादा कारपोरेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं और इसका परिणाम है उत्पादन संबंधों में चहुँमुखी रास्तों जैसे ठेका कृषि आदि के माध्यम से बदलाव। परिणामस्वरुप लघु कृषि उत्पादन पर विनाशकारी प्रभाव के साथ भूमि के बड़े भूस्वामियों /कारपोरेट लॉबी को वापस हस्तातंरण की प्रक्रिया शुरु हो गयी है जिससे बड़े पैमान पर भूमिहीन असहाय ग्रामीण सर्वहारा की सेना गुणात्मक रुप से बढ़ रही है।

कुल मिलाकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण के घटने की प्रक्रिया और तेज हुई है। साम्राज्यवादी दबाव और घरेलू स्तर पर उत्पादित विनिर्मित सामानों को विदेशी कंपनियों को आऊटसोर्स के साथ इस अक्खड़ सरकार के द्वारा बदहवाश निजीकरण की मुहिम के चलते यह और गंभीर होती जा रही है। रक्षा उत्पादन, आयात के उदारीकरण के साथ रेलवे की रोलिंग स्टॉक जरुरतों के संदर्भ में ऐसा पहले ही शुरु किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त,इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की अपनी विनिर्माण क्षमता का लगातार विनाश हो रहा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक बड़े विनाश की ओर, अंतराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और साम्राज्यवादी शक्ति पर बराबर बनी रहने वाली निर्भरता की ओर धकेला जा रहा है। यही नहीं नवउदारवादी पूंजीवादी निजाम के व्यवस्थाजन्य संकट का आर्थिक नीति परिदृश्य में एक और गंभीर असर है। वैश्विक स्तर पर और हमारे देश में भी मंदी के रुझान के कारण, क्षमता के उपयोग और बाजार संकुचलन की समस्या के कारण सामन्य उत्पादन/ वास्तविक अर्थव्यवस्था में मुनाफे का स्तर गंभीर दबाव में आ रहा है। मौजूदा आर्थिक नीति निजाम ने,दबाव में आये निजी कारपोरेट की भरपाई करने के लिए दोतरफा कदम उठाये है। एक, अर्थव्यवस्था की पूरी रोजगार प्रोफाईल में अधिक बदलावों के लिए कार्यपालिका व विधायी दोनों स्तरों से आक्रामक श्रम कानून सुधारों का है जिसमें श्रम लागत को बराबर कम रखने के लिए रोजगार का लगभग पूरी तरह अस्थायीकरण करना है और मेहनतकशों पर गुलामी के हालातों को थोपना है। दूसरे में, बहुमुखी तरीकों से निजी कारपोरेट लॉबी द्वारा राष्ट्रीय संपदा/संसाधनों व संपदा से धनी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निजीकरण करने का अडियल कदम, लाभकारी पी एस यू' में सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से नीचे पहुँचा देने की केन्दित मुहिम के चलते उनके नियन्त्रण को निजी हाथों में सौंपना, ज्यादातर पी एस यू' में भारी आऊटसोर्सिंग, अंततः निजीकरण करने के उद्देश्य से रेलवे उत्पादन इकाईयों, प्रमुख बंदरगाहों व आयुध कारखानों, का भारी

व आक्रमक कारपोरेटाइजेशन, रेलवे प्रिटिंग प्रेसों तथा केन्द्र सरकार की प्रिटिंग प्रेसों का बंद किया जाना, कारपोरेटों के पक्ष में भूमिअधिग्रहण नियमों का पुर्नगठन करने का आक्रामक कदम, कोयला व गैर कोयला खनन क्षेत्र का पूरी तरह से विनियमन, पी एस यू द्वारा भारी निवेश कर खोजे गये तेल क्षेत्रों को विदेशी एजेंसियों समेत निजी हाथों में सौंपना, संसाधनों व संपदा को देशी–विदेशी निजी कारपोरेटो द्वारा हथियाने बल्कि लूट लेने के लिए उठाये गये कुछ कदम हैं।

यह वास्तव में भाई–भतीजा पूंजीवाद का असली चेहरा है जो विकृत के साथ–साथ भ्रष्ट भी है। जिसका समूचा ध्यान राष्ट्रीय संसाधनों व संपदा को अवैध रुप से हथियाने के साथ सट्टेबाजी और उससे भी बढ़कर मजदूरों व जनता के निर्देयी शोषण पर केन्द्रित है। बिग बिजनेस/कारपोरेटो के अधिकतर अवैध ढंग से बनाये जाने वाले मुनाफे उत्पादक आर्थिक गतिविधि पर हावी हैं और राष्ट्र व जनता लगातार पिछड़ती, खोजी जा रही है। भारी पैमाने पर लगभग 10 लाख करोड़ के बैंक कर्जों (जन बचतों) का वापस न लौटाया जाना और दिवालिया कंगाली की प्रक्रिया के माध्यम से इसके बड़े हिस्से को बट्टे खाते में डाल कर कारपोरेट चोरी को वैधता प्रदान करना, पिछले पाँच वर्षों में 5.89 लाख करोड़ रुपये के परोक्ष करों की अदायगी का न होना बड़े पूंजीपतियों द्वारा अवैध फायदों के कुछ निर्लज्ज उदाहरण है। इसके ऊपर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व जनता की कीमत पर इस सारे समुदाय पर की गई कर छूटों की बारिश भी है।

यहीं नहीं, इस पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये कि अर्थव्यवस्था के संकट ने तमाम सैक्टरों में आम जनता को भारी मुसीबतों में डाल दिया है और देश भर में वे विभिन्न आंदोलनों, कार्रवाईयों व लामबंदियों के माध्यम से विरोध में सामने आ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, शासक वर्ग जनता की जनवादी अभिव्यक्ति के प्रति लगातार असहनीय होते जा रहे हैं और उनकी ऐसी असहनीयता को दो तरह से जोर देकर प्रयोग में लाया जा रहा है। एक, जनता का ध्यान उसकी मुश्किलों के वास्तविक कारणों से हटाकर, कारपोरेट वर्ग, मीडिया व राजसत्ता की मद्द से जनता के लोकप्रिय जनादेश को अपने पक्ष में विकृत/या हाईजेक करने के लिए आक्रामक साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के द्वारा ; दूसरे में जनवादी प्रक्रिया को ही कदम दर कदम रौंदना शामिल है। मगर मोड़ने या भटकाने की तिकड़में एक या दो बार ही सफल हो सकती हैं हमेशा नहीं और जनता को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। वास्तव में,नवउदारवादी व्यवस्था के संकट के गहराते जाने के साथ उसका जनवाद के साथ ज्यादा असहज और असहनशील होना तय होता है और रुझान फासीवादी आक्रामकता के साथ निरंकुशता की ओर होता है।

इसके संकेत 2014 में भाजपा शासन के आने के साथ ही मिलने शुरु हो गये थे। आर एस एस अपनी हिन्दुत्व की विचारधारा और फासीवादी प्रकृति की अपनी 'हिन्दू राष्ट्र ' की परियोजना को समाज के हर हिस्से, चाहे व शिक्षा हो, संस्कृति, सामुदायिक जीवन, खेल–कूद,वैज्ञानिक व सामाजिक संस्थानों और हर कहीं राज सत्ता के सीधे संरक्षण में अपने विभाजनकारी प्रभाव को फैलाने में बारीकी से काम कर रहा है। इस सब का उद्देश्य साम्प्रदायिक विभाजनकारी ध्रुवीकरण कर आपसी झगड़ों व विवादों का एक ऐसा माहौल बनाये रखना है जिससे वे राजनीतिक शासन पर काबिज रहें और हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक आधार को नष्ट कर सकें।

हमें चुनौती से निपटना होगा; और हम ऐसा कर सकते हैं

इसलिए, हमारे सामने चुर्नौती कहीं बड़ी है। यह चुनौती केवल मजदूरों के श्रम व ट्रेड यूनियन अधिकारों को बचाने, जनता के जनवादी व मानव अधिकारों को और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की नहीं है। हमें, साथ ही साथ शासन में बैठे नवउदारवाद के फासीवादी व अधिपत्य की मंशा वाले राजनीतिक एजेंटों के द्वारा समूचे समाज पर बरपा हमले का मुकाबला करना है। इसके साथ ही हमें आर. एस.एस व भाजपा की भटकाने व विभाजित करने वाली तिकड़मों का भी मुकाबला करना है। इस मुकाबले में मजदूर वर्ग को अगली कतार में रहना होगा और उन्हें जनता के अधिकारों, जीविका व उसकी एकता पर, अर्थव्यवस्था व समाज

पर हो रहे सभी हमलों व तिकड़मों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष की निरन्तरता के साथ समाज के अन्य तबकों से जनता को लामबंद करने की पहलकदमी व नेतृत्व करना होगा।

इसलिए हमारे समक्ष सबसे महत्वपूर्ण काम मजदूर वर्ग के आन्दोलन की एकता को व्यापक करने तथा संघर्ष को आक्रामक हस्तक्षेप की ऊंचाई की ओर ले जाने का है जिसमें केवल मेहनतकशों की माँगे ही नहीं बल्कि समूचे मेहनतकश वर्ग के मुद्दे भी शामिल हैं जिनका सबसे बड़ा शिकार मेहनतकश वर्ग है। इस संघर्ष का मुख्य आधार मजदूरों –किसानों का गठजोड़ रहेगा। हमें, आर्थिक व सामाजिक दोनों रुपों में शोषित प्रताड़ित आबादी को अपने साथ लेने के लिए अपने गठजोड़ को व्यापक करना होगा। इस व्यापक गठजोड़ को उदारवाद के खिलाफ तथा संकट के बीच बचने के लिए इसके द्वारा की जाने वाली सामाजिक –राजनीतिक जुगतों के खिलाफ समझौताविहीन लड़ाई के आधार पर बनाना होगा।

हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे

सार रुप में हमारा संघर्ष और हस्तक्षेप अवश्य ही सीधे–सीधे मेहनतकश जनता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा पूरे समाज पर हमले के खिलाफ होने के साथ ही इस चहमुखी आक्रामक ओर इसके निरंकुश, फासीवादी व विभाजनकारी आयामों व उसके पीछे की राजनीति व विचारधारा के खिलाफ भी होना चाहिये। एक, ऐसा मंच को लगातार व्यापक बनाते हुए व उसके स्तर को ऊपर ले जाते हुए जमीन पर संगठित संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से होगा और दूसरे में प्रत्येक कार्रवाई के पहले और बाद में हर मेहनतकश व आम जनता के दरवाजे पर पहुँकर नवउदारवाद की विभाजनकारी व उठा–पटक की तिकड़मों से संबंध राजनीति के जनता पर, जनवादी अधिकारों पर, प्रगतिशील मूल्यों पर इस हमलावर राजनीति का पर्दाफाश करने के माध्यम से करना होगा। मजदूर वर्ग को एक ही साथ दोनों संघर्षों–लामबंदी व राजनीतिक विचारधारात्मक ,का निर्माण व नेतृत्व करना होगा।

हम एक बहुत ही बड़ी चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पार नहीं पाया जा सकता। वह हमें एक अवसर भी देती है। यह अवसर शोषणकारी व्यवस्था और उसके इर्द गिर्द की तिकड़मों के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में मजदूर वर्ग की अग्रणी भूमिका का पुनः आविष्कार करने का है। हमें इस लड़ाई में उतरते हुए अपने आपको संगठन के सभी स्तरों पर – विचारधारात्मक, राजनीतिक व संगठनात्मक रुप से फिर से उन्मुख करना होगा। लड़ाई के अंतिम चक्र में पीछे भी हटना पड़ सकता है या हार भी हो सकती है लेकिन हमारे सामने जीतने के लिए एक युद्ध है। हमारे पास हमारी विचारधारा ही सबसे प्रभावी हथियार है। हमें अपने आपको इससे पूरी तरह लैस और इसके प्रभावी प्रयोग में पूरी महारत हासिल करनी होगी। यह किसी परिस्थिति विशेष में केवल एक उचित कार्यनीति ही नहीं; यह एक ऐसी कार्यनीति को तय करने के लिए जिसका हमारे रणनीतिक लक्ष्य के साथ सकारात्मक निर्देशात्मक जुड़ाव हो जो हमारे संविधान में निहित है ताकि हमारी दिशा भटके नहीं।

प्रथम राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र के उदय के इस शताब्दी वर्ष में और सीटू की स्थापना के पचासवें वर्ष में हमारे पास औपनिवेशिक काल से ही तमाम विपरीत स्थितियों में और दमन व अत्याचारों के खिलाफ मजदूर वर्ग के बहादुराना संघर्षों की विरासत है, उसके सबक हैं। हमारे पास संयुक्त वर्ग संघर्ष के रास्ते को कितने ही उतार–चढ़ाव में भटकाव से बचाने की कितनी ही सफलताओं का इतिहास है जिसमें सहयोगवाद, संशोधनवाद, सुधारवाद तथा शोषक वर्ग व उसके राजनीतिक एजेंटों के द्वारा कितने ही विभाजनकारी उकसावे भी शामिल रहे है। हमारे पास कॉ. बी.टी. रणदिवे, पी. राममूर्ति,ज्योति बसु, समर मुखर्जी, एम के पंधे जैसे महान दिग्गजों के द्वारा सीटू की स्थापना के बाद कार्रवाईयों में मजदूर वर्ग की पूर्ण एकता के लिए पिछले पचास वर्षों के संघर्षों की और वैचारिक रुप से दिशा– निर्देशन करने तथा '' एकता व कार्रवाई '' के ऐतिहासिक रास्ते के माध्यम से आन्दोलन को दिशा व नेतृत्व प्रदान करने वाले कई अन्य नेताओं की संपन्न विरासत है। संघर्षों व बलिदानों का यह संपन्न इतिहास, जो हमें हमारी गर्वीली विरासत है, हमें संयुक्त प्रतिरोध व मुकाबले के लिए प्रेरित करेगा, हमें विश्वास देगा। हम अवश्य ही कामयाब होंगे।

भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद

स्वदेश देव रॉय

शुरुआती उद्योगों की स्थापना ने तथा आधुनिक मजदूर वर्ग के उदय, देश में मजदूर वर्ग के संघर्षों और बलिदानों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं ने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन को प्रभावित किया और उसे आकार दिया। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की संक्षिप्त चर्चा जे.एस. मजुमदार द्वारा अपने लेख में की जा चुकी है।

वर्ग बोध की अंतर्निहित सहज–वृत्ति, ट्रेड यूनियनों के बनने के पहले दौर में हड़ताली संघर्षों सहित आधुनिक मजदूर वर्ग का स्वयंस्फूर्त संचालित आंदोलन, राश्ट्रीय मुक्ति से अभिन्न रुप से जुड़े राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्षों के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं विशेष रूप से महान अक्टूबर क्रांति, सभी ने, का भारत में पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियन के बनने में बड़ा योगदान दिया।

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद

भारत के प्रथम केंद्रीय ट्रेड यूनियन में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा, स्पष्ट देखी जा सकती थी। लाला लाजपत राय ने 31 अक्टूबर 1920 को एटक की कांग्रेस के अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा था *''भारत के मजदूर न केवल भारतीय श्रम के हितों की मजबूती के लिए ही हाथ और दिमाग जोड़ रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं।''* अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की ओर भारतीय मजदूर वर्ग के और आगे बढ़ने को 1927 के मई दिवस में देखा जा सकता है। इस घटना विकास को इस प्रकार से रखा गया था, *''इसका महत्व यह है कि भारतीय श्रमिक आंदोलन ने अपने आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है और वह अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की एकरुपता को घोषित कर रहा है।''* यह नोट करना आवश्यक है कि स्पष्ट रुप से अपने शुरुआती वर्षों में एटक ने वर्गीय संघर्षों व सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता का रास्ता पकड़ा था।

एटक की स्थापना के पहले दशक का अंतिम वर्ष

इस दौर में दो बहुत महत्वपूर्ण लेकिन परस्पर विरोधी घटनायें देखने में आयीं। मजदूर वर्ग के जुझारु संघर्षों की उठती लहरें और परिणामस्वरूप, 50,000 यूनियन सदस्यता ऊपर उठकर 2,00,325 तक जा पहुंची, गिरनी कामगार यूनियन स्पष्ट रुप से सर्वोच्च अग्रणी भूमिका की स्थिति में थी। इस प्रभावशाली घटनाचक्र के साथ ही उस दौर के ट्रेड यूनियन के इतिहास में वामपंथी नेताओं के योगदान की अपनी जगह है: *''कम्युनिस्ट हड़तालों का नेतृत्व करने में इसलिए सफल थे क्योंकि वे मजदूरों के मूड को सही भांपते थे और उन्होने उनके हितों की लड़ाई में अपने आपको अग्रणी कतार में रखा था {. . .} वे अथक कार्य करते थे, निर्भीक थे और लगनशील तथा समर्पित थे। इन गुणों का उन्हें यह लाभ मिला था और वे मजदूर वर्ग के निर्विवाद नेता बन गए थे।'' (वी बी कार्निक)*

दूसरी ओर यह दौर साम्राज्यवादी अत्याचारों की इंतिहा का दौर था। सरकारी दमन व हमले की पराकाष्ठा थी कि एसए डांगे, मुजफ्फर अहमद, एसवी घाटे, के एन जुगलेकर, एस एस मिराजकर, राधा रमण मित्रा, पी.सी. जोशी, जी. अधिकारी सहित एटक के शीर्ष 19 नेताओं को कुख्यात 'मेरठ षड्यंत्र केस' में आरोपित किया गया था।

वर्ग संघर्ष बनाम वर्ग सहयोग

जैसा कि ऊपर नोट किया गया है वर्ग संघर्ष तथा जुझारु आंदोलन में स्पष्ट तेजी तथा वर्ग संघर्ष के रास्ते पर अडिग बने रहने वालों की भूमिका की पहचान ने एटक के नेतृत्व में मौजूद वर्ग सहयोगियों को ट्रेड यूनियन आंदोलन को विभाजित करने की हद

तक पहुंचा दिया। *''नागपुर में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1929 तक हुई एटक की 10वीं कांग्रेस में स्पष्ट रुप से वाम व दक्षिणपंथी, गरमपंथी व नरमपंथी रुझान एकदम साफ नजर आ गये थे।''*

स्वागत कमेटी के अध्यक्ष, आर.एस. रुइकर ने अपने भाषण में सरकार के बर्बर अत्याचारों की चर्चा की, *''ट्रेड डिसप्यूट्स बिल से लेकर, पब्लिक सेफ्टी ऑर्डीनेन्स, मेरठ षडयंत्र केस, गिरनी कामगार यूनियन को चुप कराने की कोशिशें, गुंडा एक्ट, क्रिमिनल इन्टीमिडेशन बिल, कलकत्ते में जूट मजदूरों की हड़ताल के दौरान तथा मुंबई में गिरनी कामगर यूनियन की वैध ट्रेड यूनियन सभाओं पर पाबंदी, तथा सबसे ताजातरीने हमले में बॉम्बे के टेक्सटाइल मजदूरों के सबसे अग्रणी व जुझारु नेता कॉमरेड बीटी रणदिवे पर कुख्यात आईपीसी (राजद्रोह) की धारा 124–ए के तहत मुकदमा तथा गोलमुरी हड़ताल में पुलिस का गैरजरुरी हस्तक्षेप पिछले वर्ष चले दमन चक्र की श्रखंला की कड़ियां है।''*

किसी को भी यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिस दौर की चर्चा कर रहे हैं उसमें पूंजीवाद एक अभूतपूर्व संकट की जकड़ में था और पूंजीवादी बाजार 'एक महा आर्थिक मंदी' के दौर से गुजर रहे थे। उस स्थिति में वर्ग संघर्ष के रास्ते को छोड़ देना और कुछ नहीं मजदूर वर्ग के साथ विश्वासघात के साथ ही आत्मघाती भी होता। इस पृष्ठभूमि में वर्ग सहयोगियों ने एटक का पहला विभाजन कराया, जब उन्होंने (वर्ग सहयोगियों ने) उन यूनियनों के साथ जो *''शुद्ध रूप से केवल ट्रेड यूनियन लाइन'' पर काम करना चाहती थीं,* इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन' की शुरूआत की थी।

एटक के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एटक की दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस में अपने भाषण में कहा था, *''हम पर अक्सर वर्ग युद्ध की वकालत और वर्गों के बीच की दूरी को बढ़ाने का आरोप लगाया जाता है। पूंजीवाद का धन्यवाद कि दूरी काफी ज्यादा है, और इस बारे में पूंजीवाद का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड सकता {. . .} वर्ग युद्ध कोई हमारी देन नहीं है। यह पूंजीवाद की देन है और जब तक पूंजीवाद रहेगा यह भी रहेगा।'* इसके लिए कुछ भी दिखाने बताने के बजाय इसे व्यक्ति की अपनी समझ पर छोड़ दें। यह जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला संयोग है कि ट्रेड यूनियन में विभाजन – राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष और वर्ग सहयोग के बीच विवाद के कारण हुआ।

डब्ल्यू एफ टी यू की स्थापना

3 अक्टूबर 1945 को पेरिस कांग्रेस में स्थापित, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (वुफ्टू), ट्रेड यूनियनों का पहला वास्तविक एकीकृत इन्टरनेशनल फेडरेशन है। वुफ्टू की स्थापना से विश्व मजदूर आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आया। अपनी स्थापना से ही यह विश्व ट्रेड यूनियन संगठन अपने पूर्ववर्ती संगठनों से बिलकुल भिन्न था। *''वुफ्टू एकता का शिशु है, फासीवाद के विरुद्ध मजदूरों के संयुक्त संघर्षों का, शांति स्थापित करने की इच्छाशक्ति का और औपनिवेशिक जनता की मुक्ति का, बेहतर जीवन की स्थितियों के लिए संघर्षों का, शोषणकारी इजारेदारों और जंगखोरों के विरुद्ध लड़ाईयों का''* इन शब्दों के साथ वुफ्टू के संस्थापक महासचिव लुइस सेलॉट ने वुफ्टू की स्थापना को परिभाषित किया था। उस समय भारत की अकेली केन्द्रीय ट्रेड यूनियन एटक का प्रतिनिधित्व वुफ्टू की इस कॉंग्रेस में एस.ए. डांगे ने किया था जिन्हें वुफ्टू के स्थापना महाधिवेशन में उपाध्यक्ष चुना गया था।

वुफ्टू को अस्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र

वर्ग संघर्षों के मूलाधारों पर स्थापित, वुफ्टू शुरूआत से ही, उस व्यापक पूंजीवाद–विरोधी, साम्राज्यवाद–विरोधी आंदोलन का हिस्सा था जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही दुनिया के बहुत से भागों में खड़ा हुआ था। साम्राज्यवादी शक्तियां जानती थीं कि मजदूर वर्ग की पक्की अंतर्राष्ट्रीय एकता को तोड़े बिना, जो वुफ्टू की स्थापना के द्वारा प्राप्त की गयी थी, विश्व भर में मजदूर वर्ग को बांटने के उनके कुटिल ऐजेंडे को पूरा करना संभव नहीं था। यूरोप में व दूसरे स्थानों पर ट्रेड यूनियन आंदोलन को बांटने के लिए किस प्रकार अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा राज्य व पैसे की ताकत को लगाया गया यह बाद में सामने आ गया। उदाहरण के लिए, 1950 और 1954 के बीच सीआईए के सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल आर्गेनरइजेसंस के निदेशक थॉमस डब्ल्यू ब्रेडेन ने 1967

में सेटरडे इविनिंग पोस्ट के लिए लिखा थाः *''1947 में, कम्युनिस्ट सीजीटी ने पेरिस में एक हड़ताल की, जिसने फ्रांस की इकोनोमी को ठप्प करने की स्थिति पैदा कर दी। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार गिर जाएगी . . . संकट के बीच, इरविंग ब्राउन सामने आया।* {यह आदमी कुख्यात अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर फ्री लेबर डेवलपमेंट का निदेशक था जिसे विशाल अमेरिकी संकाय से पैसा दिया गया था और जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआइए) का युद्ध के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेटर था।} *ड्यूबिंसकी ट्रेड यूनियन (एएफएल – एड) के पैसे से ''फोर्स औवियर'' को एक गैर–कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित किया गया। जब पैसा खत्म हो गया, तो वह सीआईए की ओर मुड़ा। इस प्रकार, फ्री ट्रेड यूनियनज्मि को गुप्त मदद की शुरूआत हुई . . . इसके बिना युद्ध के बाद के इतिहास का रास्ता कुछ और ही होता . . .।''*

वर्ग सहयोगियों को वुफ्टू से अलग किया गया

वर्ष 1947 में अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने कुख्यात ''ट्रूमैन सिद्धांत'' के माध्यम से अपने आपको 'दुनिया का पुलिसवाला' घोषित करते हुए यह अधिकार ले लिया कि वह इस दुनिया में ऐसी किसी भी सरकार के विरुद्ध हस्तक्षेप कर सकता है जो उसे पसंद न हो। इसके साथ ही उस समय के अमेरिकी विदेश मंत्री जनरल मार्शल ने यूरोप के तथाकथित पुनर्निर्माण के लिए इस योजना को अमरीकी कांग्रेस में पेश किया जिसे 'मार्शल योजना' के नाम से जाना जाता है। असलियत में तो मार्शल–प्लान एक ऐसी योजना थी जो पूंजीवादी यूरोप को अमेरिकी आर्थिक व राजनीतिक संरक्षण में लेने के लिए थी।

वुफ्टू की एक्जीक्यूटिव ब्यूरो की 19 जनवरी 1949 को हुई बैठक में विभाजन हो गया। ब्रिटिश टीयूसी के अध्यक्ष आर्थर डेकिन ने ''12 महीने के लिए वुफ्टू की सभी गतिविधियों को निलंबित किए जाने'' की माँग करते हुए एक पत्र पढ़ा, ऐसा किये जाने पर ब्रिटिश टीयूसी वुफ्टू से बाहर चली जाएगी। अमेरिकी जेम्स बी कैरी कहीं ज्यादा अक्खड़ थाः *''दिखावा करने का कोई फायदा नहीं, वुफ्टू एक लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। आइये हम इसे दफना दें।''* प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और ब्यूरो के इस फैसले के बाद आर्थर डेकिन, जेम्स बी. कैरी और ई. कुपर्स (नीदरलैंड) बैठक छोड़कर चले गए।

वुफ्टू को विभाजित करने वाले वर्ग सहयोगियों ने दिसंबर 1949 में लंदन में इन्टरनेशनल कंफेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन (आईसीएफटीयू) की शुरुआत की। फ्रांस की सरकार ने पेरिस में वुफ्टू मुख्यालय को बंद कर उसे वियना जाने को मजबूर करने के माध्यम से वुफ्टू को तोड़ने वालों की मदद की। सारी दुनिया के और विषेशकर अमेरिकी पूंजीपतियों ने वुफ्टू में विभाजन की वाह–वाही की।

हालांकि वुफ्टू में विभाजन का तात्कालिक कारण 'मार्शल प्लान' के बारे में परस्पर विरोधी रुख था, लेकिन वुफ्टू में कई सारे सवालों पर बुनियादी अंतर इसके पहले ही उभर कर सामने आ चुके थे। विवाद का मुख्य बिन्दू साम्राज्यवादी ताकतों की दादागीरी का विरोध और ट्रेड यूनियनों की भूमिका के इर्द–गिर्द था।

आई.सी.एफ.टी.यू. व डब्ल्यू.सी.एल. का विलय

नवंबर 2006 की शुरुआत में, वियना में, वैचारिक स्तर पर एक जैसे लेकिन कामकाज में एक दूसरे के प्रतियांगी संगठन – इन्टरनेशनल कंफेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन तथा वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ लेबर ने एक साथ आ कर इन्टरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन (आई.टी.यू.सी.) बनायी। इस विलय के पीछे दोनों घटकों का कुल मानना यह था कि राजनीतिक संस्थानों व बिजनेस तथा बाजारों के वैश्वीकरण के साथ ही ट्रेड यूनियनों का भी वैश्वीकरण हो। स्पष्ट है कि यह एक वर्ग सहयोगी दृष्टिकोण था तथा इन संगठनों और इनके विलय ने इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन आंदोलन के समक्ष एक सुधारवादी चुनौती को खड़ा किया, विशेषकर वर्गीय रुप से उन्मुख वुफ्टू के सामने जिसे एक क्रांतिकारी नजरिये के साथ स्थापित किया गया था।

समाजवाद को धक्का और वुफ्टू

सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवाद के ढ़ह जाने के बाद, वुफ्टू काफी हद तक कमजोर हो गया। पूर्ववर्ती समाजवादी देशों में घटे राजनीतिक और वैचारिक धटनाचक्र ने भी वुफ्टू को गंभीर रुप से प्रभावित किया। यह (वुफ्टू) वर्ग संघर्ष की नीतियों

से बड़े स्तर पर भटक गया तथा पूंजीवादी शोषण से मानवता की पूर्णमुक्ति के लिए सामाजिक बदलाव का अभियान व प्रोपेगेंड़ा मंद पड़ गया। साम्राज्यवादी शक्तियों ने वुफ्टू को अस्थिर करने के लिए बाहर व अंदर से कई चहुमुखी षड़यंत्र रचे। स्पष्ट वित्तीय दिक्कत ने भी वुफ्टू के कामकाज पर असर डाला। टीयूआई ट्रांसपोर्ट के महासचिव ने संगठन की समूची संपत्ति को कब्जा लिया।

तथापि, जिस प्रकार सूर्य–ग्रहण स्थायी रूप से सूर्य को नहीं ग्रस सकता है, साम्राज्यवादी तिकड़में भी वुफ्टू को उसकी वर्गीय उन्मुखता व मजदूर वर्ग के प्रति वचनबद्धता की स्थापना शपथ से स्थायी रुप से अलग कर पाने में असफल रहीं। वुफ्टू की हवाना कांग्रेस ने इसे फिर से पटरी पर ला दिया। हम हवाना काँग्रेस के बाद से वुफ्टू के भीतर घटे घटनाक्रम पर इस लेख में बाद में चर्चा करेंगे।

सीटू की स्थापना

सीटू की स्थापना के लिए बाध्यता पैदा करने वाली पृष्ठभूमि की चर्चा एम. के. पंधे व हेमलता के लेखों में की जा चुकी है। तथापि यह बहुत ही उपयोगी होगा कि हम उन कारकों की समानता व जमीनी सच्चाई पर गौर करें जो 1929 में एटक के विभाजन तथा 1970 में सीटू की स्थापना और 1949 में वुफ्टू के विभाजन के पीछे थे। कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी थी कि मजदूर वर्ग संकटग्रस्त पूँजीपति वर्ग के जबरदस्त हमले की चपेट में था और समय की माँग थी कि मजदूर वर्ग की शक्तिशाली एकता हो और वर्ग–संघर्ष तेज हो। मगर वर्ग सहयोगियों ने वर्ग संघर्ष का रास्ता छोडकर तब के पूंजीपति वर्ग व सत्ताधारियों से सहयोग कर आश्चर्यजनक रुप से मजदूर वर्ग की चिंताओं तथा उनके जीवन व जीविका के मुद्दों का समझौता किया।

तथापि, इसमें असमानताएँ भी थीं। इसमें यह था कि या तो वर्ग सहयोगियों ने टूट कर संगठन छोड़ा या वर्ग संघर्ष के पक्षधरों को मजबूर किया। बाद वाली स्थिति के चलते सीटू की स्थापना हुई। मगर, दोहराने के लिए, जो साझे बिन्दु दांव पर थे, वे थे, वर्ग संघर्ष के रास्ते पर चलकर संघर्ष के लिए एकता का निर्माण करके मजदूर वर्ग के जीवन और आजीविका पर पूंजीपति वर्ग के हमलों का मुकाबला करना।

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के लिए सीटू की प्रतिबद्धता

अपने स्थापना सम्मेलन में जिस नारे तथा दृष्टिकोण व संघर्ष के रास्ते का सीटू ने उद्घोष किया था वह थाः 'एकता और संघर्ष', तथा वर्ग संघर्ष के रास्ते के माध्यम से मौजूदा बुर्जुवा–भूस्वामी निजाम को जनता के जनवादी राज में बदलने के लिए लड़ाई। हम दोहरा सकते हैं कि वर्ग संघर्ष के तीन घटक हैंः आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक। इस व्यापक समझदारी के तहत यह समझना आवश्यक है कि वर्ग संघर्ष और सर्वहारा अंर्तराष्ट्रीयवाद एक दूसरे से संबद्ध हैं, पूरक हैं, सम्पूरक हैं।

हम भारत के मजदूर वर्ग के आंदोलन के जन्म से ही उसके वर्ग संघर्ष व अंर्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण की सम्पन्न विरासत के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बाद में समझौतावादी दौर आया और उसके परिणामस्वरुप घटे घटनाक्रम में सीटू की स्थापना भी शामिल है। इसलिए, सीटू द्वारा वर्ग संघर्ष और सर्वहारा अंर्तराष्ट्रीयतावाद की सम्पन्न विरासत को आगे बढ़ाना एक तार्किक बिन्दु है।

सीटू के अंर्तराष्ट्रीय संबंधों के शुरुआती दिन

सीटू के अंर्तराष्ट्रीय संबंधों को उनकी शुरुआत से ही अलग–अलग दौर में बांटा जा सकता है। शुरु के दिनों में ये संबंध मुख्यतः समाजवादी देशों के साथ थे। सीटू के सबसे पहले विदेश गये प्रतिनिधिमंडल के रुप में बी.टी.आर. ने उत्तरी वियतनाम (वियतनाम की सम्पूर्ण मुक्ति और एकीकरण से पहले) के ट्रेड यूनियन संगठन के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फरवरी 1974 में वहाँ की यात्रा की थी। जे.एस. मजुमदार ने 1975 में पोलैंड में टीयूआई (आयल, केमीकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज) के सम्मेलन में भाग लिया था। वियतनाम की मुक्ति के बाद, वुफ्टू ने 1978 में केमिकल और बैक्टीरियो–लोजीकल वैपन्स के खिलाफ एक 'विश्व सम्मेलन' का आयोजन हो ची मिन्ह सिटी में किया था। जे.एस. मजुमदार ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। विमल राणदिवे ने 1979

में सोफिया में आयोजित विश्व कामकाजी महिला सम्मेलन में भाग लिया। 1989 में सीटू के प्रतिनिधिमंडल ने बुल्गारिया के केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के सम्मेलन में भाग लिया, उसी वर्ष सीटू ने कोसाटू के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की जो दक्षिण अफ्रीकी जनता की रंगभेद के खिलाफ लड़ाई व मुक्ति संघर्ष के प्रति सीटू की मजबूत एकजुटता का परिचायक था। सीटू ने 24 फरवरी 1990 को दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संघर्ष के किवंदंती बन गये नेता नेल्सन मंडेला की रिहाई की खुशी में इण्डियन ट्रेड यूनियन्स अगेन्स्ट अपारथाइड के बैनर तले हुए समारोह में अग्रणी भूमिका निभाई। जनवरी 1990 में क्यूबा के सी.टी.सी. के आमंत्रण पर एम. के. पंधे और ई.बालनंदन ने क्यूबा की यात्रा की।

हालांकि सीटू औपचारिक रूप से वुफ्टू से संबद्ध नहीं था, फिर भी अपनी स्थापना से ही उसने वुफ्टू के साथ नजदीकी संबंध बनाऐ रखे यहाँ तक कि उसने सभी बैठकों और सम्मेलनों में भाग लिया है और वुफ्टू के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया। सितंबर 1989 में वुफ्टू के मॉस्को में आयोजित अंतिम सम्मेलन में भाग लेने गये प्रतिनिधिमंडल में एम.के. पंधे, पी.के. गांगुली, ए.के. पद्मनाभन व अन्य शामिल थे। उस दौरान पंधे के नेतृत्व में सीटू के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मास्को की यात्रा की थी और एक अन्य मिशन लेक्चर टूर टू मास्को में आर. उमानाथ ने मास्को की यात्रा की थी, इन दोनों का आमंत्रण सोवियत संघ की ट्रेड यूनियन ए.यू.सी.सी.टी.यू. ने दिया था।

आगे की ओर छलांग का दशक

2000–2010 का दशक सीटू के अंर्तराष्ट्रीय संबंधों में आगे की ओर छलांग का दशक रहा। इस दौरान द्विपक्षीय बिरादराना संबंधों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। इस दौर में सीटू ने कई ऐतिहासिक अंर्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों का भारत में आयोजन किया। इस दौर में सीटू के सम्मेलनों में अंर्तराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही।

27– 31 दिसंबर, तक हैदराबाद में आयोजित सीटू के 10वें सम्मेलन की महासचिव की रिपोर्ट के अंर्तराष्ट्रीय हिस्से में नोट किया गया था, ''सीटू ने अपने 9वें सम्मेलन के बाद से अपने अंर्तराष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने में बड़ी छलांगे लगायी हैं। एक प्रमुख ट्रेड यूनियन केंद्र के रुप में जो हाल के वर्षों में वैश्वीकरण और उदारवाद के खिलाफ संघर्ष की अगली कतार में खड़ा रहा है, सीटू ने मजदूर वर्ग के बीच एकजुटता कायम करने और विश्व बैंक, अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बहुराष्ट्रीय निगमों के हमलों का विरोध करने के लिए लगभग सभी प्रमुख अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और बैठकों में भाग लिया है। इस बारे में सीटू की समझदारी रही है कि जब तक हम विदेशों में हमारे बिरादराना संगठनों के साथ नजदीकी संबंध नहीं बनाते, उनके साथ आदान–प्रदान कर उनके अनुभवों से नहीं सीखते, तब तक हम अपने देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो सकते।

तेल और प्राकृतिक गैस मजदूरों के पेरिस विश्व सम्मेलन में भागीदारी

आज सीटू या कहें कि पी.जी.डब्ल्यू.एफ.आई. के जो मजबूत अंर्तराष्ट्रीय संबंध हैं उसकी उत्पत्ति 18–20 अक्टूबर 1999 को पेरिस में फ्रांस के एफ.एन.आई.सी.–सी.जी.टी., लीबिया के ओ.सी.आर. यूनियन ऑफ मेडिटेरेनियन और आई.ई.एम.ओ. पेरिस द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित आयल एंड पेट्रोलियम वर्कर्स के विश्व सम्मेलन से है।. भारत से इसमें जो एकमात्र प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था वह सीटू का था जिसमें स्वदेश देव रॉय, टीएस रंगराजन और स्वपन मित्रा शामिल थे। 36 देशों के 140 प्रतिनिधि सम्मेलन में थे।

इस सम्मेलन से हमें, विश्व तेल व पेट्रोलियम सेक्टर के ट्रेड यूनियन आंदोलन के बीच काफी कुछ समझने व आदान–प्रदान का अवसर मिलाा। पेरिस सम्मेलन के बाद अगले कदम के रुप में आयल एंड पेट्रोलियम वर्कर्स का दूसरा विश्व सम्मेलन 08–10 मार्च 2003 को कोलकाता में हुआ। हमारे द्वारा आयोजित तेल और पेट्रोलियम मजदूरों का यह कार्यक्रम मील का पत्थर था। सम्मेलन को सभी संदर्भों में भारी सफलता मिली। भारत व विदेशों से 124 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ज्योति बसु, तत्कालीन केंद्रीय

तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नाइक तथा अध्यक्ष और महासचिव सहित सीटू सचिव मंडल के कई सदस्यों ने सम्मेलन में शिरकत की थी।

उपरोक्त कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम के रुप में पी.जी.डब्ल्यू.एफ.आइ. का स्थापना सम्मेलन नवम्बर 2005 में हल्दिया में हुआ जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, मिस्र, यूनान, लीबिया, ट्यूनीशिया व बांग्लादेश से 19 बिरादराना प्रतिनिधियों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

ऊपर दर्ज की गई अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अलावा, सीटू ने कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किये। इनमें सीटू ने 14–16 दिसंबर 2007 को अंतर्राष्ट्रीय खनिकों के सम्मेलन की सह–मेजबानी कोलकाता में की।

सीटू के द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम 19–23 अप्रैल, 2008 तक कोच्चि में सदर्न इनिशिएटिव ऑन ग्लोबलाईजेशन एंड फॉर ट्रेड यूनियन राइट्स (एस.जी.टी.यू.आर.) की 8वीं कॉंग्रेस का आयोजन था। इससे पहले कोच्चि में सीटू ने इन्टरनेशन एनर्जी एंड माइनर्स आर्गेनाइजेशन (आइ.ई.एम.ओ.) के अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी तथा इसमें पंधे को आइ.ई.एम.ओ. का सह–अध्यक्ष चुना गया था।

सीटू का 12वाँ सम्मेलनः एक मजबूत मील का पत्थर

जहाँ तक सर्वहारा अंर्तराष्ट्रीयतावाद पर सीटू के नीतिगत दृष्टिकोण का संबंध है, इस बारे में 17–21 जनवरी 2007 को बैंगलोर में हुआ सीटू का 12वाँ सम्मेलन एक से अधिक कारणों से सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसमें 'अंर्तराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन' शीर्षक से एक नीति पत्र सम्मेलन में आयोग के तहत चर्चा में पेश किया गया था। इसमें 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 50 ने चर्चा हिस्सा लिया था। ए.के. पद्मनाभन ने सत्र की अध्यक्षता और स्वदेष देव रॉय ने पर्चा प्रस्तुत किया था। आयोग में चर्चा के निष्कर्ष के साथ सीटू के अंर्तराष्ट्रीय संबंधों पर एक दस्तावेज को सम्मेलन के सत्र में पारित किया गया था।

12वें सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि

इस सम्मेलन की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि इसमें विदेशी प्रतिनिधियों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। 27 देशों से 51 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। जिन देशों का प्रतिनिधित्व था उसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, चीन, क्यूबा, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, यूनान, हंगरी, इटली, जापान, लीबिया, मॉरीशस, मैक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, स्पेन, श्रीलंका, सीरिया, थाईलैंड, यूके, अमरीका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और वेनेजुएला शामिल थे।

सीटू के 12वें सम्मेलन में इतने अधिक देशों के बिरादराना प्रतिनिधियों की उपस्थिति एक नये आयाम के रुप में थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी क्यूबा, वेनेजुएला, चीन और वियतनाम के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी। हमारे पड़ोसी देश भी पूरी ताकत से इसमें मौजूद थे। अफ्रीका और अरब क्षेत्र के कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। ए.एफ.एल.–सी.आई.ओ. में विभाजन के बाद अमेरिका में नए उभरे ट्रेड यूनियन सेन्टर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। इसी तरह यूरोप का प्रतिनिधित्व भी अच्छा–खासा था और इसमें यूरोप के औद्योगिक रुप से विकसित कई देश शामिल थे। ब्रिटिश टी.यू.सी. ने हमारे सम्मेलन में पहली बार भाग लिया।

वुफ्टू के नवनिर्वाचित महासचिव, जॉर्ज मावरिकोस की उपस्थिति सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिए बड़े उत्साह की बात थी। आई.एल.ओ. की ओर से नई दिल्ली स्थित इसके सब रीजनल आफिस के निदेशक व वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल थे तथा आई.एल.ओ. की गवर्निंग बॉडी से दो मजदूर सदस्य भी शामिल थे।

विदेशी प्रतिनिधियों का विशेष सत्र

अलग–अलग देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय चर्चाओं के अलावा, सम्मेलन में सभी विदेशी प्रतिनिधियों व सीटू के सचिवमंडल का एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया था। अपनी शुरुआती टिप्पणी में, एम.के. पंधे ने हमारे देश के मुद्दों व संघर्षों के बारे में सीटू की समझदारी तथा मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता के सवाल पर हमारे दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला था।

हवाना में वुफ्टू का 15वाँ महाधिवेशन

वुफ्टू का 15वाँ महाधिवेशन 1 से 4 दिसंबर 2005 तक हवाना, क्यूबा में हुआ था। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, सोवियत संघ के ढह जाने के बाद वुफ्टू के संगठन की दशा के लगातार बिगड़ते जाने के बाद, इसका 15वाँ सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस 15वाँ अधिवेशन से वुफ्टू ने अपने संगठन को ताकत देने के रास्ते पर बढ़ने की इसकी सामूहिक व जनवादी कार्यप्रणाली को विस्तार देने तथा अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर मजदूरों से जुड़े सभी मुद्दों पर अपनी गतिविधियों को तेज करने की पुनः शुरुआत की।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ट्रेड यूनियन शिक्षा, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के सेमीनारों केंद्रीय कार्यालयों में ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण स्कूलों आदि के माध्यम से वुफ्टू की विचारधारात्मक मजबूती को गतिविधियों में प्राथमिकता पर रखा गया है। इस प्रक्रिया में युवा मजदूरों के साथ ही कामकाजी महिलाओं पर प्राथमिकता के तहत ध्यान दिया गया। इसके साथ ही साम्राज्यवाद की सभी तिकड़मों के विरुद्ध एवं एक संकल्प वाला अभियान, प्रोपेगेंडा व संघर्ष आज वुफ्टू की पहचान बन गये हैं; और इसी तरह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी।

वुफ्टू के संविधान के अनुसार इसके सभी सामूहिक निकायों के नियमित व प्रभावी कामकाज को संगठन के जनवादी व सामूहिक सिद्धांतों के साथ सुनिश्चित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा सेक्टवार मंचों – वुफ्टू ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल (टी.यू.आइ.) के कामकाज में लगातार सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। वुफ्टू की औपचारिक संबद्धता हासिल करने से पहले से ही, सीटू, नए नेतृत्व की पहलकदमियों के अनुरुप अपनी ओर से पूरी कोशिश करता रहा है।

सीटू वुफ्टू से संबद्ध हुआ

सीटू की नासिक में 2010 में हुई जनरल काउंसिल बैठक में सीटू को वुफ्टू से संबद्ध करने का प्रस्ताव पारित हुआ। वुफ्टू के महासचिव ने सीटू के फैसले को औपचारिक मान्यता देने के लिए नई दिल्ली में सीटू केंद्र, का दौरा किया। सीटू के 14वें सम्मेलन की महासचिव की रिपोर्ट का उद्धरण है :–

''हमारे 13वें सम्मेलन के बाद से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटना विकास हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (वुफ्टू) से हमारा औपचारिक रुप से संबद्ध होना है। विस्तृत में जाए बिना इतना कहा जा सकता है कि सीटू के पूर्ण सचिवमंडल, वर्किंग कमेटी, तथा जनरल कौंसिल में वुफ्टू के साथ संबद्धता को लेकर लम्बा विचार विमर्श हुआ। नवंबर 2010 में सीटू का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वुफ्टू मुख्यालय गया। सचिवमंडल ने नवंबर 2010 की अपनी बैठक में, नासिक में जनवरी 2011 में होने वाली जनरल कौंसिल बैठक में वुफ्टू से संबद्ध होने के फैसले का प्रस्ताव पेश करने का फैसला लिया।''

''नासिक जनरल काउंसिल की बैठक ने सीटू को वुफ्टू से संबद्ध करने का प्रस्ताव पारित किया। वुफ्टू के साथ सीटू की संबद्धता के महत्व की सराहना करते हुए, वुफ्टू महासचिव, कॉमरेड जॉर्ज मावरिकोस ने एथेन्स में होने वाली वुफ्टू की 16वीं कांग्रेस की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजूद समय निकालकर फरवरी 2011 में व्यक्तिगत रुप से सीटू मुख्यालय का दौरा किया और संबद्धता के हमारे

प्रार्थनापत्र को प्राप्त किया। सीटू को संबद्धता प्रदान करने के फैसले की घोषणा कॉमरेड मावरिकोस द्वारा एथेन्स में वुफ्टू की 16वीं कांग्रेस में की गई जिसका कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया।''

वुफ्टू के विभिन्न मंचों – सचिवालय/सचिवमंडल, अध्यक्षीय परिषद, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा विभिन्न ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल (टीयूआई) में हमारी उपस्थिति व योगदान अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन में दिखाई पड़ता है। लगभग सभी टीयूआई में सीटू के प्रतिनिधि सचिवमंडल में हैं। विभिन्न मंचों व पदों पर हमारे साथी सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सीटू की साख बढ़ा रहे हैं। वुफ्टू के सबसे महत्वपूर्ण मंच – वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और वार्षिक अध्यक्षीय परिषद की बैठकों में हमारी उपस्थिति व भागेदारी को अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिलती रही है। और इसमें रत्ती भर भी अतिश्योक्ति नहीं है।

निसन्देह, मजदूर वर्ग की विचारधारा के प्रति सीटू की प्रतिबद्धता, वर्ग संघर्षों के रास्तेकी पालना तथा मजदूर वर्ग के हितों के लिए लड़ने का जुझारुपन ऐसे कारक हैं जिनसे सीटू को अंतर्राष्ट्रीय सराहना व प्रतिष्ठा मिली है।

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं

आज मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझने के लिए, यह समझना आवश्यक है कि साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के तहत, राष्ट्रों की सीमाओं के आर–पार होने वाली पूंजी दुनिया के हर कोने में आ–जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व अर्थव्यवस्था को कब्जाये हुए हैं। इसके मुख्य लक्षणों को पूंजी के विशाल संकेंद्रण व केन्द्रीयक्रत होने में, उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीयकरण में, बहुराष्ट्रीय एकाधिकार तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन की विशाल क्षमता के साथ लगातार विकसित हो रही नई प्रोद्योगिकी पर साम्राज्यवादी नियंत्रण के रुप में देखा जा सकता है।

इस परिस्थिति में मजदूर वर्ग के आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय एकता की अभूतपूर्व व फौरी जरुरत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नव–उदारवाद से लड़ने के लिए आवश्यक हो गयी है। साम्राज्यवादी खेमे के पिछलग्गू राष्ट्रों के शासक वर्ग, अंततः, साम्राज्यवादी एजेंसियों के बताये रास्ते का पालन कर रहे हैं। आज मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के मूल जोर की दिशा आवश्यक रुप से साम्राज्यवाद–विरोधी होनी चाहिए।

हमें अवश्य ही याद रखना चाहिए कि ''वैश्वीकरण साम्राज्यवादी होने के साथ ही एक वर्गीय परिघटना है।'' ये घटनायें स्पष्ट रुप से पुष्टि करती है कि वित्तीय पूंजी संचालित साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के हमले का मुकाबला करने के लिए 'वर्ग संघर्ष और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद' अभिन्न व पूर्व शर्त है। मजदूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीयतावाद के प्रति अपने कर्तव्य पालन में जाने–अनजाने किसी भी तरह की ढ़ील का अर्थ वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के संदर्भ में समझौता करना होगा।

आज सीटू की विश्व ट्रेड यूनियन आंदोलन में बड़ी प्रतिष्ठा है। अपने संगठन के हर एक स्तर पर हमें समझना चाहिए कि वर्ग संघर्ष और सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयता के प्रति सीटू की वचनबद्धता सीटू के झंडे को ऊंचा रखे हुए है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लगातार विस्तार और मजबूती वर्ग संघर्ष के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की कसौटी है।

इस बुनियादी कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन ही हमें वित्तीय पूंजी संचालित साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के खिलाफ संघर्ष में मजदूर वर्ग को एकजुट करने की भूमिका को निभाते जाने में सक्षम तथा सारी दुनिया में पूंजीवादी वर्ग द्वारा आगे बढ़ाई गई वर्गीय लड़ाई में खासतौर पर पूंजीवाद के लगातार जारी संकट के वर्तमान दौर में मुकाबला करने में सक्षम बनाता है।

'सीटू के 50 साल' व भारत में 'प्रथम केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के 100 वर्ष' के अवसरों को मनाते हुए, आओ हम अपने आपको सीटू के जन्म की शपथ – एकता व संघर्ष के उद्देश्य के साथ वर्ग संघर्ष व सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के प्रति पुनः समर्पित करें।

राज्य सरकार कर्मचारियों की एकता और संघर्ष

l Hkk"k ykck

अधिकारों का संघर्ष

ब्रिटिश सरकार, सरकारी कर्मचारियों को भारत की जनता का शोषण करने और उस पर शासन करने के औजार के रूप में देखती थी। अतः तत्कालीन सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलनों से दूर रखने के भरसक प्रयास करती थी। सरकारी कर्मचारियों को आन्दोलनों से दूर रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन पर कठोर नियम कानून लागू किए, लेकिन इन कठोर आदेशों व नियमों के बावजूद कर्मचारियों ने अलग–2 समय में संगठन बनाकर विभिन्न आन्दोलनो में हिस्सा लिया।

सरकारी कर्मचारियों की आजादी को सीमित करने वाला पहला सरकारी प्रस्ताव 1873 में पास किया जो कर्मचारियों को अखबार के प्रकाशन, प्रबंधन व संपादन पर रोक लगाता था। 1890 में गृह विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र द्वारा कर्मचारियों को राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई और 1876 में सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों पर और प्रतिबंध लगा दिए गए। अब कर्मचारी सरकारी नीति से सम्बंधित किसी भी मामले पर बोलकर या लिखकर विचार प्रकट नहीं कर सकता।

भारत में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी नियुक्त थे तथा सरकार कर्मचारियों के बीच राजनैतिक संक्रमण के खतरे के प्रति पूरी सचेत थी। खतरे से बचने के लिए 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली तैयार की गई। बाद में उसके प्रावधानो को और कठोर बनाकर कर्मचारियों को जनसभा, प्रदर्शनों व हड़ताल में भाग लेने पर रोक लगा दी गई।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बावजूद इन अलोकतांत्रिक नियमों को खतम नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 310 में राष्ट्रपति या राज्यपाल या फिर सरकार को कर्मचारियों को दंड देने का असाधारण अधिकार है। यहां अनुच्छेद इंगलैंड में संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर तैयार किया गया था। धारा 311 (2) की उपधारा सी के तहत प्राधिकरण किसी भी कर्मचारी को बिना कारण बताए व बिना आत्मरक्षा का अवसर दिए पद अवनति व बर्खास्त कर सकता है।

लेकिन पिछले 70 वर्षों के दौरान हुए अनुभव बताते हैं कि सरकार द्वारा विशेषाधिकारों का प्रयोग ट्रेड यूनियन आन्दोलन को विफल करने के लिए और सत्तारुढ़ दल के राजनैतिक षडयंत्र को पूरा करने और कर्मचारियों को उत्पीडन करने हेतु किया गया। धारा 311 (2) बी का प्रयोग पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कश्मीर, हरियाणा व अन्य प्रांतों के कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने के लिये बार–बार किया गया है। रेलवे प्राधिकरण में 1974 में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बाद तबाही ला दी। इस धारा का प्रयोग आन्दोलनकारी कर्मचारियों पर आज भी किया जा रहा है।

कर्मचारी संगठनों को मान्यताः सर्वप्रथम ब्रिटेन के डाक कर्मियों की यूनियन को 1899 में मान्यता मिली। भारत में इंडियन टेलीग्राफ एसोसिएषन के गठन के बाद कर्मचारी संगठनों की मान्यता का प्रष्न 1906 में उठा तथा बहुत संघर्ष के बाद 13 अक्तूबर, 1921 को भारत सरकार ने कर्मचारियों के संगठन को मान्यता देने का पत्र जारी किया। जिसके लिए नियम तालिका तैयार की गई।

वार्ता का अधिकारः ब्रिटेन में संगठन को सम्बंधित विभाग द्वारा मान्यता के जरिए अपने सदस्यों की ओर से वार्ता करने का अधिकार प्राप्त था। मगर भारत में यह अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि दमन की नीति अपनाई गई। 1960 में कर्मचारियों द्वारा की गई देशव्यापी हड़ताल के बाद कर्मचारियों को यह अधिकार 1966 में दिया गया।

बढ़ता आन्दोलन और संगठन का निर्माण

प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के तहत और वर्श 1917 के रूसी नवम्बर क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में न केवल मजदूरों की यूनियन गठित हुई, बल्कि देश के विभिन्न स्थानों में केन्द्रीय व राज्य सरकारी कर्मचारियों के संगठनों का भी जन्म होने लगा। सबसे पहले बंगाल में ऑल बंगाल मिनिस्टोरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का गठन फरवरी 1920 में हुआ। इसके अलावा बंगाल में कर्मचारियों

के 2 अन्य संगठन भी गठित हुए। 4 जून, 1920 को राइटर्स बिल्डिंग के डायरेक्टर व सैक्रेट्रीएट के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से राइटर्स बिल्डिंग एसोसिएशन का गठन किया।

इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों में भी प्रांतीय कर्मचारियों के संगठन गठित हुए। लेकिन इन संगठनों में उच्च स्तरीय चेतना का अभाव था। आजादी मिलने से पूर्व कुछ निश्चित क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलनो ने जुझारू रूप लेना शुरू कर दिया था। जैसे 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का गोरवपूर्ण विद्रोह हुआ व इस विद्रोह के सर्मथन में मुंबई के लाखों मेहनतकशों ने हड़ताल की। इन कार्यवाहियों से आजादी का आंदोलन और तेज हुआ। दूसरी तरफ डाक व टेलीग्राफ कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल हुई, जिसके फलस्वरूप प्रथम वेतन आयोग का गठन हुआ। इन दोनों वीरतापूर्ण संघर्षों से राज्य के तमाम कर्मचारी संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित हुए। उसके बाद 1947 में आजादी मिलने के बाद राज्य सरकारी कर्मचारियों की पहली हड़ताल मद्रास प्रेसिडेन्सी में की गई। उसके बाद बंगाल में कर्मचारियों के जुझारू संघर्ष हुए। फायर सर्विस श्रमिकों ने स्वतंत्रता के पूर्व 28 फरवरी, 1946 को 800 कर्मचारियों की छंटनी के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही (हड़ताल) शुरू की व 11 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद विजय हुई और हड़ताल को समाप्त किया गया। 8 जनवरी, 1946 से बंगाल गवर्नमेंट प्रैस श्रमिकों ने ओवरटाइम भत्ते की मांग पर हड़ताल शुरू कर दी। 3 जनवरी, 1948 का राशनिंग कर्मचारियों ने एक दिन की पैन डाउन हड़ताल का पालन किया। 9 मार्च, 1949 को रेलवे कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी।

आजादी मिलने के बाद पहले केन्द्रीय वेतन आयोग के सिद्धांतों व महंगाई भत्ते के फार्मूले, वेतन निर्धारण मानकों के कारण पूरे देश के कर्मचारियों में काफी रोष फैल गया। वेतन तथा महंगाई के प्रश्नों के अलावा ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई निरंकुश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ भी अत्याधिक रोष पैदा हुआ। औद्योगिक श्रमिकों के जुझारू संघर्ष से प्रेरित होकर विभिन्न राज्यों में सरकारी कर्मचारियों ने भी ट्रेड यूनियन कार्यवाही शुरू कर दी। इस समय कर्मचारियों का मुख्य नारा महंगाई भत्ता और वेतनमान में संशोधन था। सरकारों द्वारा कर्मचारियों के आन्दोलन को कुचलने के लिए आचरण नियमावली का प्रयोग करके उनका दमन किया गया, लेकिन यह दमन आन्दोलनों को रोकने में असफल रहा।

केन्द्रीय कर्मचारियों से राज्य सरकारी कर्मचारियों की स्थिति ज्यादा दयनीय थी। पुराना व मनमाना वेतनमान तथा सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इससे कर्मचारियों में काफी असंतोष फैल गया। इस असंतोष ने राज्य कर्मचारियों के आन्दोलनों को जन्म दिया। लेकिन इन संघर्षों का नेतृत्व राज्य के विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाता था, जिनका कोई देशव्यापी संपर्क नहीं था। राज्यों के स्तर पर भी विभिन्न कर्मचारियों की राज्यव्यापी एकता ने कोई आकार ग्रहण नहीं किया था। सभी कर्मचारियों की राज्य आधारित मांगों को आधार बनाकर राज्यव्यापी संघर्ष के लिए संयुक्त मंच का गठन किया गया था, लेकिन वो ज्यादा सदृढ़ नहीं था। यह राज्यव्यापी एकता का विकासकाल था। इससे कर्मचारी संकुचित दायरे से आगे बढ़े तथा उनकी ट्रेड यूनियन चेतना का विकास हुआ। संघर्षों से शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि उनकी मांग व मुद्दे देश की आर्थिक व अन्य नीतियों से जुड़े हैं। उनकी समस्याएं व अन्याय देश की आर्थिक व सामाजिक नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन नीतियों में राज्य सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था। इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए विभिन्न राज्यो के कर्मचारी नेताओं के मन में अखिल भारतीय मंच का गठन करने का विचार आया। इस बीच दक्षिण और उत्तर के राज्य सरकारी कर्मचारियों का तालमेल करने के प्रयास किए गए लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। दरअसल अखिल भारतीय मंच के लिए राज्य कर्मचारियों का भारतव्यापी संघर्ष तैयार करना जरूरी था। लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय मंच का गठन कोई आसान कार्य नही था। फिर भी आन्ध्र प्रदेश एनजीओ एसोसिएशन व उनके शीर्ष नेता श्रीरामुलु ने संगठन गठित करने के विशेष प्रयास किए। उन्होंने 1958–59 के दौरान सभी राज्य सरकारी संगठनों के बीच संपर्क स्थापित किया तथा सभी राज्यस्तरीय संघर्षों को समन्वित और एकजुट करने के लिए राष्ट्र स्तरीय संगठन बनाने पर सहमति बनाई।

अंततः 23–24 जनवरी, 1960 को हैदराबाद में आयोजित एक सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का गठन किया गया। प्रथम सम्मेलन के बाद मार्च 1961 में हैदराबाद में एक और सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्रीरामुलु को महासचिव चुना गया। इसमें 13 राज्यों ने हिस्सा लिया था। मूल्य वृद्धि, आवश्यकता आधारित न्यूनतम वेतन, पदोन्नति, अवकाश तथा अनुच्छेद 311 (2) क, ख, ग के प्रावधानों का उन्मूलन सम्मेलन में बहस के मुख्य बिन्दु थे।

उसके बाद निरंतरता से देश के कर्मचारियों की मांगों पर अखिल भारतीय स्तर पर कार्यवाहियां हुई। वर्तमान दौर में अ.भा.रा.स.क. महासंघ की सदस्यता संख्या 60 लाख है तथा यह संगठन देशभर के कर्मचारियों का नेतृत्व करता है। अ.भा.रा.स.क. महासंघ

की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक तिहाई संख्या महिलाओं की है। अ.भा.रा.स.क. महासंघ का जन्म असल में ट्रेड यूनियनों के जन्म की पृष्ठभूमि में ही हुआ।

मजदूर वर्ग के साथ व्यापक एकता

प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में वरसाइल शांति करार हुआ, जिसमें श्रमिक आन्दोलन को स्वीकृति देने के लिए सन 1919 में लीग ऑफ नेशन के अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जन्म हुआ। करार के हस्ताक्षर के बाद कर्मचारियों के संगठन के अधिकार को मान्यता देने का प्रश्न अप्रतिरोध्य बन गया। कर्मचारी संगठनों को भी मान्यता मिली।

1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को मुंबई के श्रमिकों ने भारी समर्थन दिया तथा 1946 में ही डाक व टेलीग्राफ कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन एआईटीयूसी द्वारा किया गया। इंडियन लेबर कांफ्रेंस के 15वें अधिवेशन में आवश्यकता आधारित न्यूनतम वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए। इन निर्णय ने श्रमिकों व कर्मचारियों को तीव्र कार्यवाहियां करने के लिए उत्तेजित किया। केन्द्र सरकार की नीतियों का प्रभाव न केवल कर्मचारियों की मांगों बल्कि आम जनता व मजदूरों की मांग पर भी पड़ता है। दोनों के आन्दोलनों पर सरकार द्वारा दमन विरोध की कार्यवाहियां भी की जाती रही है। इसलिए अलग–2 प्रकृति के मंच होने के बावजूद सामूहिक संघर्ष भी होते रहे हैं। 28 अगस्त, 1974 को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के तत्वाधान में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अ.भा.रा.स.क. महासंघ ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 18 अप्रैल, 1977 को सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय महासंघों द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कन्वेंशन का आयोजन किया गया। बिहार नॉन गजेटेड फेडरेषन ने फरवरी 1978 में धारा 310 और 311 (2) ए,बी,सी के उन्मूलन पर राश्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विशिष्ट न्यायविदों, केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं और विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में अनुच्छेदों का उन्मूलन, कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन अधिकारों और राजनैतिक अधिकारों की मांग रखी गई। यह पहला मौका या जब लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रश्न पर विशेष रूप से एक ट्रेड यूनियन द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया।

हड़ताल के अधिकार के लिए आम हड़तालः तामिलनाडु में जयललिता सरकार की कर्मचारी विरोधी नितियों के खिलाफ वहां के कर्मचारी व षिक्षक 2 जुलाई,2003 क हड़ताल पर चले गए तथा जयललिता सरकार ने दो लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद अगस्त 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को गैरकानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ व तामिलनाडु कर्मचारियों पर हुए हमले के विरोध में 24 फरवरी, 2004 को देषव्यापी हड़ताल की गई, जिसमें लगभग पांच करोड़ मजदूरों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

अ.भा.रा.स.क. महासंघ ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर 17 अंतर्राष्ट्रीय हड़तालों का पालन किया है व सरकारों को संयुक्त मांग पत्र भेजे हैं। महासंघ भविष्य में भी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन में शामिल होकर संघर्षों को मजबूत करने के लिए दृढ संकल्प है। अभी 17वीं लोकसभा के परिणाम आए हैं तथा सत्ता घोर दक्षिणपंथी हाथों में चली गई है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें और गंभीर चुनौतियो का सामना करना होगा तथा उसी अनुरूप अपनी रणनीति बनाते हुए बड़े आन्दोलनों का निर्माण करना होगा।

एकता एवं संघर्ष

ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इम्पलाईज फैडरेशन अपने गठन से ही एकता एवं संघर्ष के साथ आगे बढता गया है। फैडरेशन की आज 26 राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों में चुनी हुई राज्य कमेटियां हैं। फैडरेशन ने जहां राज्य कर्मचारियों को संगठित किया, वहीं केन्द्रीय कर्मचारियों एवं वर्करों की कंफडरेशन के साथ समन्वय स्थापित किया। फैडरेशन ने संघर्षों के दम पर ही सभी केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को राज्यो में लागू करवाने के अतिरिक्त हड़ताल करने के अधिकार की भी रक्षा की। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इम्पलाईज फैडरेशन ने देश की केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर की गई आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों में शामिल होकर कर्मचारियों एवं मजदूरों की व्यापक एकता में अपना योगदान दिया और सभी राष्ट्रव्यापी आम हड़तालों में शिरकत की। फैडरेशन ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा, तमिलनाडू, महाराष्ट्र आदि अलग–अलग राज्यों में राज्य सरकारों के दमन के खिलाफ पूरे देश में एकजुटता कार्यवाहियां करते हुए राज्य सरकारों को आन्दोलनरत्त संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर भी किया है। फैडरेशन केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नव उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ और जनसेवाओं को बचाने के लिए निरंतरता में व्यापक एकता के साथ संघर्ष किए।

(सुभाष लांबा एआईएसजीईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

राज्यों से

पंजाब

पंजाब रोडवेज के ठेका मजदूरों की हड़ताल

पूरे पंजाब रोडवेज की सार्वजनिक सड़क परिवहन प्रणाली को राज्य भर में ठप्प करते हुए, सीटू की पन बस यूनियन के ठेका मजदूर 2–4 जुलाई को हड़ताल पर थे। बस डिपो पूरी तरह से सुनसान रहे। हड़ताली कर्मचारियों ने रैलियां निकालीं, धरना और प्रदर्शन किए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हड़ताली कर्मचारियों की जनसभाओं को सीटू और यूनियन के राज्य और जिला नेताओं ने संबोधित किया। मुख्य मांगें हैं, ठेका प्रणाली को समाप्त करना और उनकी नौकरियों को नियमित करना, सुप्रीम कोर्ट के 'समान काम के लिए समान वेतन' का कार्यान्वयन, आदि हैं। परिवहन ठेका मजदूरों की मांगों और हड़ताल के समर्थन में ए.आइ.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के ज्ञापन पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी और ज्ञापन को परिवहन मंत्री को अग्रेशित किया तथा तदनुसार ए.आइ.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. को सूचित करना है।

3 जुलाई को, पन बस के ठेका मजदूर यूनियन ने परिवहन मंत्री के गृह शहर मलेरकोटला में एक विशाल राज्य स्तरीय रैली की। रैली के बाद, मजदूरों ने परिवहन मंत्री के आवास तक एक मार्च का आयोजन किया।

अंततः, परिवहन मंत्री, जो चंडीगढ़ में थे, ने 9 जुलाई को हड़ताली मजदूरों की मांगों पर यूनियन और सीटू के साथ बैठक करने का स्थानीय प्रशासन के माध्यम से एक लिखित आश्वासन दिया। प्रस्तावित चर्चा के मद्देनजर, यूनियन ने प्रस्तावित चर्चा के परिणाम तक हड़ताल को टाल दिया।

(द्वारा: रघुनाथ सिंह और आर. लक्ष्मैया)

उद्योग एवं क्षेत्र

सामाजिक योजनाएँ

मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत के खिलाफ आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा देशव्यापी विरोध;

10 जुलाई अखिल भारतीय विरोध दिवस

सीटू की आंगनवाड़ी कर्मचारी फेडरेशन, ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के आह्वान पर, 22 राज्यों – पूर्व में असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड; – उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान; – पश्चिम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात और दक्षिण में आंध्र प्रदेष, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक और केरल में लाखों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बिहार के मुजफ्फरपुर में, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एइएस) के कारण 150 से अधिक कुपोषित बच्चों की मौत होने के खिलाफ 10 जुलाई को देश भर में विरोध प्रदर्शन किये। और ऑल इंडिया डिमांड डे पर ''कोई और मुजफ्फरपुर नहीं; कुपोशण मुक्त भारत के लिए; आइसीडीएस को मजबूत करने के लिए; और स्वतंत्रता के वादे को पूरा करने के लिए नारे लगाये।''

उस दिन पूरे देश में, आंदोलनकारी मजदूरों ने रैली और जनसभा आयोजित करने से पहले, मुजफ्फरपुर में अपनी जान गंवाने वाले मासूम बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त किया। मुजफ्फरपुर में, सैकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारियों और सहायकों ने विरोध रैली में भाग लिया। हाल ही में आयोजित आंगनवाड़ी बिहार राज्य यूनियन के सम्मेलन ने मुजफ्फरपुर में कुपोषण के खिलाफ और आइसीडीएस को मजबूत करने के लिए वार्षिक अभियान चलाने निर्णय लिया जो 14 अगस्त से शुरू होने वाला है।

नई एनडीए–भाजपा सरकार के खिलाफ यह पहली राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाही थी, जो एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी के खिलाफ जिसमें बच्चों को पूरक पोषण आहार नहीं दिया गया था और बिहार सहित कई राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान महीनों से नहीं किया गया है।

पिछले संसदीय चुनाव से पहले और उसके दौरान, आरएसएस–बीजेपी सोषल मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार कर रही थी, कि उनका वेतन रु०18,000 तक बढ़ गया है। लेकिन, मोदी –2 सरकार का बजट, मुजफ्फरपुर त्रासदी के बाद भी टज्ञठस्भ्डभ्एस के लिए आवंटन नहीं बढ़ा। इसके अलावा, कई राज्यों को बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान करना बाकी है, जैसा कि सितंबर 2018 में पीएम मोदी द्वारा घोषित किया गया था। कई राज्य सरकारें स्कूलों में प्री–स्कूल खोल रही हैं, इस प्रकार बच्चों को आंगनवाड़ियों से दूर ले जा रही हैं। कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और केंद्रीकृत रसोई का भी प्रयास किया जा रहा है।

पिछले संसदीय चुनाव से पहले और उसके दौरान, आरएसएस–बीजेपी, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार कर रही थी कि उनका वेतन बढ़कर रु०18,000 तक हो गया है। लेकिन, मोदी–2 सरकार के बजट में, मुजफ्फरपुर त्रासदी के बाद भी आइसीडीएस के लिए आवंटन नहीं बढ़ाया है। इसके अलावा, कई राज्यों को बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान करना बाकी है, जैसा कि सितंबर 2018 में पीएम मोदी द्वारा घोषित किया गया था। कई राज्य सरकारें स्कूलों में प्री–स्कूल खोल रही हैं, इस प्रकार बच्चों को आंगनवाड़ियों से दूर ले जा रही हैं। कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और केंद्रीकृत रसोई का भी प्रयास किया जा रहा है।

10 जुलाई के माँग दिवस में शामिल माँगें इस प्रकार हैं – आइसीडीएस को स्थायी बनाया जाये; आइसीडीएस के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हो; न्यूनतम वेतन रु०18,000 से कम न हो; आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 45वीं आईएलसी द्वारा अनुशंसित सामाजिक सुरक्षा और पेंशन लाभ देय हों; आइसीडीएस का कोई भी निजीकरण न किया जाये; आइसीडीएस में कॉरपोरेट कंपनियों और कॉरपोरेट एनजीओ की भागीदारी न हो; आइसीडीएस को मजबूत करें; आंगनवाड़ियों को आंगनवाड़ी–कम–क्रेच में परिवर्तित किया जाये; पोषण के लिए आवंटन में वृद्धि की जाये; आइसीडीएस में पूर्वस्कूली शिक्षा को मजबूत करके उसे बनाए रखा जाये।

एक अपील

असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड जल्द भेजें

18 जुलाई को, सीटू ने देश के मजदूरों से असम की जनता के साथ एकजुटता में खड़े होने की अपील की, जो विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहे हैं, और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करें। सीटू असम राज्य कमेटी बचाव और राहत कार्यों में पूरी तरह से शामिल है।

असम के कुल 33 जिलों में से 30 बाढ़ प्रभावित हैं; 18 जुलाई तक 36 इंसानी जिन्दगियाँ समाप्त हो चुकी हैं; 54 लाख लोग विस्थापित हैं; 90 प्रतिशत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पानी में डूबा है; ब्रह्मपुत्र का जल स्तर राज्य भर में खतरे के स्तर से ऊपर उठ गया है। विभिन्न स्थानों पर सड़कें, पुल, पुलिया और कई अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा है।

सीटू ने अपनी सभी राज्य कमेटियों, फेडरेशनों और संबद्ध यूनियनों से आह्वान किया कि वे तुरंत धन जुटाऐं और सीटू की असम राज्य कमेटी को उसके बैंक खाते में धन हस्तांतरण के माध्यम से जल्द से जल्द भेजें और सीटू केंद्र को इसकी सूचना भेजें।

सीटू की असम राज्य कमेंटी के बैंक खाते का विवरण

सीटू असम राज्य कमेटी,

खाता संख्याः 0303010014036

यूबीआई शाखा, उलुबरी

आइ.एफ.एस.सी.– UTBIOULU319

तपन सेन

महासचिव

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568; आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ

  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,

  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com

  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

एएसपी, एसएसपी और वीआइएसएल की बिक्री के विरोध में

(रिपोर्ट पृ. 7)

प्रवेश को रोकते हुए एएसपी, दुर्गापुर में *(बांये)* **और एसएसपी, सलेम में** *(दांये)*

एकजुटता में बी.एच.इ.एल., त्रिची

चैन्ने में संयुक्त ट्रेड यूनियन रैली

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication -05/08/2019)

रेलवे के निजीकरण का विरोध

(रिपोर्ट पृ. 5)

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डी.एल.डब्ल्यू.), वाराणसी

मुम्बई

चैन्ने

डी.आर.इ.यू . द्वारा चैन्ने व मदुरै में

अनारा व नागपुर में ए.आइ.एल.आर.एस.ए. द्वारा 24 घंटे की भूख हड़ताल

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : के हेमलता